Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

E-Mail : mantrabharatmumbai@gmail.com, Mo. 7007837917

संस्करण : मुंबई
वर्ष : 10
अंक : 295
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00
शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज एवं ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित एवं ठाणे, नवी मुम्बई, पालघर, नासिक एवं पुणे से प्रसारित

3 रा. सु. गवई के कार्यों का सम्मान करते हुए ...
4 भारत-कनाडा संबंध : सुधार की दिशा में ...
7 ट्रेनिंग के दौरान हादसा, 17 साल के ...

संक्षिप्त न्यूज

मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ में ऐए का पथ संचलन, कर्नाटक में कांग्रेस को नई चुनौती

बैंगलुरू। कर्नाटक के यादगिरी ज़िला प्रशासन ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पूर्व विधानसभा क्षेत्र गुरमितकल में आरएसएस के पथ संचलन के लिए सशर्त अनुमति दे दी है। 31 अक्टूबर को होने वाला यह संचलन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी शर्तों के साथ होगा। अधिकारियों के अनुसार, इस आयोजन पर दस शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें भड़काऊ नारे लगाने, हथियार ले जाने और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने पर प्रतिबंध शामिल है। यह संचलन नरेंद्र राठौड़ लेआउट से शुरू होकर सम्राट सर्कल, बसवेश्वर सर्कल, हनुमान मंदिर और कुंभारवाड़ी जैसे प्रमुख स्थानों से होकर गुज़रेगा।
गौरतलब है कि गुरमितकल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गढ़ और गृह क्षेत्र है। खड़गे इससे पहले आठ बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं। आरएसएस के जिला प्रचार प्रमुख बसप्पा संजानोल ने 23 अक्टूबर को एक आवेदन के माध्यम से मार्च की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने जुलूस को सम्राट सर्कल, एपीएमसी सर्कल, हनुमान मंदिर, मराठावाड़ी, पुलिस स्टेशन रोड, मिलन चौक और सिहिनीरू बावी मार्केट मेन रोड से होते हुए राम नगर में समाप्त होने की अनुमति दे दी है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी नियम का उल्लंघन किया गया, तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।

मुजफ्फरपुर में गरजे पीएम मोदी!

आरजेडी का मतलब 'कट्टा, क्रूरता, कुशासन का जंगलराज'

मुजफ्फरपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर में एक रैली के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) पर तीखा हमला बोला और उस पर बिहार को 'जंगल राज' के युग में धकेलने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि राजद का शासन 'कट्टा (बंदूक), क्रूर (क्रूरता), कटुता (कड़वाहट), कुशासन (कुशासन) और भ्रष्टाचार' से भरा रहा है। उन्होंने लोगों से ऐसी राजनीति को नकारने और आगामी विधानसभा चुनावों में विकास और स्थिरता का समर्थन करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राजद पर भी हमला बोलते हुए उन पर राजनीतिक लाभ के लिए छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने छठी मैया के बारे में विपक्ष की कथित टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा, 'क्या कोई चुनाव में वोट के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या बिहार और देश की जनता ऐसा अपमान बर्दाश्त करेगी?' उनकी टिप्पणी पर दर्शकों ने ज़ोरदार तालियाँ बजाईं।
इस त्योहार के सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'हमारी सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।' उन्होंने आगे कहा कि यह त्योहार 'मानवता और भक्ति के उत्सव' के रूप में वैश्विक मान्यता का हकदार है।

एक हल्के-फुल्के अंदाज़ में, प्रधानमंत्री मोदी ने मुजफ्फरपुर के लोगों और वहाँ की उपज की प्रशंसा करते हुए कहा, 'यहाँ की लीची जितनी मीठी होती है, उतनी ही मीठी है यहाँ की बोली।' भीड़ ने, खासकर महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या ने, उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। आगामी बिहार चुनावों में समर्थन का आह्वान करते हुए, उन्होंने अपने चिरपरिचित नारे 'फिर एक बार, एनडीए सरकार!' के साथ मतदाताओं से आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी के बीच सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी छठ गीत प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि युवा छठ गीतों की समृद्ध विरासत से और गहराई से जुड़ें। ये भक्ति गीत इस त्योहार के मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते हैं।'
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रतियोगिता में पूरे भारत के कलाकार शामिल होंगे, जिससे 'नई आवाज़ें, नए गीत और भक्ति की नई अभिव्यक्तियाँ उभरेंगी।' उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आस्था और प्रकृति के इस पवित्र उत्सव को वैश्विक मंच पर उचित स्थान मिले। यह प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम छठ महापर्व को यूनेस्को द्वारा मानवता को एकजुट करने वाले त्योहार के रूप में मान्यता दिलाने के लिए दृढ़ हैं।' उन्होंने कहा, 'भारत माता की जय' के नारों के बीच।

दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग पर 'फिजूलखर्ची' की, सौरभ भारद्वाज बोले- जनता का पैसा बर्बाद

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को दिल्ली सरकार पर क्लाउड सीडिंग पहल पर करदाताओं के करोड़ों रुपये बर्बाद करने का आरोप लगाया और इसे बेकार का नाटक करार दिया। एएनआई से बात करते हुए, भारद्वाज ने दावा किया कि पर्यावरण मंत्रालय, सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), आईएमडी (भारतीय मौसम विभाग) और सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) सहित कई विशेषज्ञ एजेंसियों ने पहले ही सलाह दी थी कि इस मौसम में दिल्ली में कृत्रिम बारिश संभव नहीं है और इससे स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है।
आप नेता ने कहा कि स्पष्ट रूप से, दिल्ली सरकार ने करदाताओं के करोड़ों रुपये एक बेमतलब के नाटक पर बर्बाद कर दिए। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्री, सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), आईएमडी (भारतीय मौसम विभाग) और सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) की विशेषज्ञ राय थी कि इस मौसम में दिल्ली में कृत्रिम बारिश संभव नहीं है और इसके परिणामस्वरूप लोगों को बीमारियाँ हो सकती हैं। भारद्वाज ने आगे कहा कि जब दिल्ली सरकार को यह रिपोर्ट 6 से 8 महीने पहले मिली थी, तो वह इस पर पैसा कैसे खर्च कर सकती थी? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को इसका जवाब देना चाहिए।

क्लाउड सीडिंग एक उन्नत मौसम परिवर्तन विज्ञान है, जिसका उद्देश्य विमान या अन्य साधनों का उपयोग करके सिल्वर आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे चुनिंदा कणों को उपयुक्त बादलों में डालकर वर्षा को प्रेरित या बढ़ाना है। दिल्ली सरकार ने अपनी मज़बूत वायु गुणवत्ता प्रबंधन रणनीति के तहत लगातार दो क्लाउड सीडिंग अभियान पूरे किए।

चक्रवात के दौरान बापटला चर्च में फंसे 15 लोगों को बचाया गया: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बृहस्पतिवार को कहा कि बापटला जिले के एक स्थानीय चर्च में फंसे 15 लोगों को हाल ही में आए भीषण चक्रवात 'मोंथा' के दौरान स्थानीय लोगों और बचाव दलों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया, 'बापटला जिले के पारचूर स्थित होसन्ना चर्च में फंसे 15 लोगों को स्थानीय निवासियों और बचाव टीमों ने मदद की गुहार मिलने के बाद करीब 15 मिनट में बचा लिया।'
नायडू ने बचाव कार्य में शामिल सभी लोगों की सराहना की। मुख्यमंत्री द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में देखा गया कि चर्च में फंसे लोग कमर तक पानी में चल रहे थे। उन्हें बचावकर्मियों ने एक लंबी रस्सी के सहारे बाहर निकालने में मदद की, ताकि वे मजबूती से पकड़ बनाए रखते हुए बाढ़ के पानी को पार कर सकें। अंततः सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। दक्षिणी राज्य हाल ही में आए भीषण चक्रवात 'मोंथा' से प्रभावित हुआ था, जिसका अर्थ थाई में 'सुगंधित फूल' होता है।

न्याय के नए नायक! जस्टिस सूर्यकांत बने देश के अगले मुख्य न्यायाधीश, 24 नवंबर से नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति कांत 23 नवंबर को सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई के सेवानिवृत्त होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। वह देश के 53वें सीजेआई होंगे और 9 फरवरी, 2027 तक 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक पोस्ट में कहा कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत को 24 नवंबर, 2025 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं। मैं उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
10 फ़रवरी, 1962 को हरियाणा के हिसार में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 मई, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के

न्यायाधीश बने। वे उन पीठों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, पर्यावरण और लैंगिक समानता पर कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस ऐतिहासिक पीठ का हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था और निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई प्राथमिकी दर्ज न की जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से बिहार में 65 लाख बहिष्कृत मतदाताओं का विवरण सार्वजनिक करने का आग्रह किया, जिससे चुनावी पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता प्रदर्शित हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का निर्देश देकर भी इतिहास रचा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत उस पीठ का हिस्सा थे जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ??की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय समिति गठित की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों में 'न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग' की आवश्यकता होती है। उन्होंने रक्षा बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को संवैधानिक रूप से वैध बताते हुए उसे बरकरार रखा और सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की स्थायी कमीशन में समानता की माँग वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी।

ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी को राहुल की चुनौती: हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाएं

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का हवाला देते हुए उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की। बिहार के नालंदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि 1971 के युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी अमेरिका से न डरीं और न ही उनके आगे झुकीं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के पास न तो कोई दृष्टिकोण है और न ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना करने की क्षमता। गांधी ने कहा, '1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को डराने और धमकाने के लिए अपने विमान और नौसेना भेजी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम आपकी नौसेना से नहीं डरते, आपको जो करना है वो करें, हमें जो करना है वो हम करेंगे।'
राहुल गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी एक महिला थीं, लेकिन उनमें इस आदमी से ज्यादा हिम्मत थी। नरेंद्र मोदी कायर हैं। उनके पास न तो कोई विजन है और न ही अमेरिका के राष्ट्रपति के

सामने खड़े होने की क्षमता। मैं उन्हें चुनौती देता हूं: अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है, तो बिहार की किसी भी सभा में उन्हें कहना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने (पीएम मोदी) उनके सामने नहीं झुका और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका। वह ऐसा नहीं कर सकते। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंगलवार को फिर से यह दावा करने के बाद सामने आई है कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था।
दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग के सीईओ लंच में बोलते हुए, ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता ने इस साल की शुरुआत में दोनों परमाणु-सशस्त्र देशों के बीच शत्रुता को रोका था। अपने हमलों को जारी रखते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का 50 बार 'अपमान' किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी का 50 बार अपमान किया है। ट्रंप ने कहा - मैंने मोदी से फोन पर 'ऑपरेशन सिंदूर' रोकने के लिए कहा था। नरेंद्र मोदी ने दो दिनों के भीतर 'ऑपरेशन सिंदूर' रोक दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि 'अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं।' नरेंद्र मोदी को ट्रंप से मिलना था, लेकिन वह डर के मारे उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं; वह छिपे बैठे हैं। नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है।

मतदाता सूची में धांधली के आरोप पर महाराष्ट्र का विपक्ष एकजुट, एक नवंबर को निकालेगा महारैली मार्च

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी दल अब एकजुट होकर चुनावी तैयारियों में लगे हैं। मतदाता सूची में धांधली के आरोपों को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) एक नवंबर को मुंबई में संयुक्त विरोध मार्च निकालेंगे। ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे के साथ शरद पवार इस विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे।
गुरुवार को मुंबई के वाय बी चव्हाण केंद्र में ठाकरे बंधुओं और शरद पवार की बैठक में इस मार्च की रूपरेखा तय की गई। बैठक में कांग्रेस नेता नसीम खान, किसान और कामगार पार्टी के जयंत पाटिल और वामपंथी दलों के नेता भी मौजूद थे। शिवसेना (यूबीटी) नेता अनिल परब ने बताया कि यह मार्च साउथ मुंबई के फैशन स्ट्रीट से शुरू होकर बीएमसी मुख्यालय तक निकाला जाएगा। दोपहर एक बजे से चार बजे तक चलने वाले इस मार्च के दौरान जनता को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
अनिल परब ने कहा कि यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और इसका मकसद मतदाता सूची में अनियमितताओं और वोट चोरी जैसे गंभीर मुद्दों को

उजागर करना है। विपक्ष का दावा है कि राज्य की मतदाता सूचियों में करीब एक करोड़ फर्जी मतदाता दर्ज हैं। इन त्रुटियों के कारण ग्रामीण और शहरी निकाय चुनावों की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों की मांग है कि राज्य निर्वाचन आयोग तुरंत मतदाता सूची की जांच और सुधार करे।
महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट मशीनों के इस्तेमाल का कोई प्रावधान नहीं है। इस पर अनिल परब ने कहा कि विपक्ष आयोग की इस दलील का अध्ययन कर रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि यह तर्क निराधार है, क्योंकि 2017 में नांदेड़ वाघाला नगर निगम चुनाव में एक वार्ड में वीवीपैट परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस संयुक्त विरोध में पूरी तरह शामिल होगी और यह मुद्दा राहुल गांधी खुद उठा चुके हैं।
इससे पहले भी शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और एमएनएस नेताओं ने राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट नामों की शिकायत की थी। आयोग ने जवाब दिया कि किसी भी राजनीतिक दल को मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है

तेलंगाना सरकार में अजहरुद्दीन के मंत्री बनने पर भाजपा ने फंसाया पेंच, चुनाव आयोग को दी शिकायत

हैदराबाद।तेलंगाना के रेवंत रेड्डी मंत्रिमंडल में कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को जगह मिल सकती है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना में कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अब भाजपा ने अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है।
भाजपा ने गुरुवार (30 अक्तूबर) को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने के प्रस्ताव को आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन बताया गया, हालांकि आदर्श आचार संहिता पूरे शहर पर लागू नहीं होती।
पार्टी ने दावा किया है कि यह 11 नवंबर को होने वाले जुबली हिल्स उपचुनाव से पहले अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण है. भाजपा ने अपने ज्ञापन में कहा कि उनके (अजहरुद्दीन) शामिल होने से जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भाजपा की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया, 'यह प्रस्ताव आगामी जुबली हिल्स उपचुनावों में मतदाताओं के एक वर्ग को लुभाने और उनके वोट हासिल करने के अलावा और कुछ नहीं है। इस स्तर पर यह प्रस्ताव आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। हालांकि आदर्श आचार संहिता पूरे हैदराबाद शहर पर लागू नहीं होती, फिर भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई कोई भी कथित घोषणा जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।'
सूत्रों के अनुसार पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है।

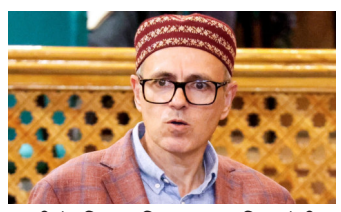

शिक्षकों की बर्खास्तगी अदालतों के माध्यम से होनी चाहिए: शिक्षकों की बर्खास्तगी पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने के आरोप में हाल ही में दो सरकारी स्कूल शिक्षकों की बर्खास्तगी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने उचित प्रक्रिया का पालन करने और व्यक्तियों को अदालत में अपना बचाव करने का अवसर देने के महत्व पर ज़ोर दिया। अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने हमेशा यह कहा है, और मैं इसे फिर से दोहराता हूँ। बर्खास्तगी अदालतों के माध्यम से होनी चाहिए। सभी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए।
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सभी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए इस्तेमाल की जा रही यह व्यवस्था उन्हें अपनी सफाई देने का मौका नहीं देती... इसलिए, बेहतर होगा कि जो लोग वास्तव में दोषी हैं, उन्हें दंडित करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि केवल संदेह के आधार पर उनके खिलाफ की गई कोई भी कार्रवाई हम

सभी के लिए हानिकारक साबित होगी।' जेकेएनसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के हवाले से कहा, 'दोष केवल अदालत में ही साबित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (सीएडी) ने गुरुवार को एक आदेश में कहा, 'उपराज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उप-खंड (सी) के तहत इस बात से संतुष्ट हैं कि राज्य की सुरक्षा के हित में, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, स्वर्गीय मोहम्मद इकबाल डार के पुत्र, वार्ड नंबर 1, खेओरा, जिला राजौरी निवासी, माजिद इकबाल डार के मामले में जाँच करना समीचीन नहीं है।' सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है, 'तदनुसार, उपराज्यपाल स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक, माजिद इकबाल डार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करते हैं।'
उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) द्वारा राज्यसभा के लिए नामित तीन उम्मीदवारों पर भी विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करेंगे।

चिराग पासवान ने कांग्रेस को घेरा, कहा- बिहारियों के अपमान पर बजाते हैं ताली

पटना। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को कांग्रेस पर बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और कहा कि जब दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ 'दुर्व्यवहार' होता है, तो उसके नेता ताली बजाते हैं। लोजपा (रामविलास) प्रमुख 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रचार अभियान में

हिस्सा लेने के लिए छपरा में थे। एएनआई से बात करते हुए, पासवान ने कहा कि मैंने राजनीति में प्रवेश इसलिए किया क्योंकि दूसरे राज्यों में बिहारियों का अपमान किया जाता है। जिस तरह से 'बिहारी' शब्द को भी गाली में बदल दिया गया था, और दुख की बात है कि सभी सत्तारूढ़ दल इसी स्थिति में थी। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि कैसे पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री, गांधी परिवार के एक सदस्य की उपस्थिति में, बिहारियों को पंजाब में प्रवेश न करने की धमकी दे रहे थे, जबकि कांग्रेस के सदस्य तालियाँ बजा रहे थे।
चिराग पासवान ने का कि यह सब दिखाता है कि जब कांग्रेस तेलंगाना में बिहारियों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, तो वे वोट मांगने बिहार कैसे आ सकते हैं? बल्कि, जनता को पूछना चाहिए, जब आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों में बिहारियों को गाली देते हैं, तो ये लोग ताली बजाते हैं, और वही कांग्रेस नेता यहां आते हैं। पासवान ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव बिहार के विकास के एक नए दौर की शुरुआत का प्रतीक होंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव और अगले पाँच साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होंगे।

मुंबई में बंधक संकट का नाटकीय अंत, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया; आरोपी रोहित आर्या ढेर

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई के पवई इलाके में गुरुवार को तनावपूर्ण बंधक स्थिति का नाटकीय अंत हो गया, जब कथित तौर पर आरोपी रोहित आर्या की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। आर्या, जिसने पहले आरए स्टूडियो के अंदर कई बच्चों को बंधक बनाया था, पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया और उसे जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बाद में उसकी मौत हो गई। मुंबई के पवई इलाके में कई बच्चों के अपहरण के आरोपी रोहित आर्या की बंधकों को छुड़ाने के लिए पुलिस की कार्रवाई के दौरान गोली लगने से मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार, जब पुलिस बाथरूम के रास्ते आरए स्टूडियो में दाखिल हुई, तो आरोपी एयर गन से लैस था और उसके पास कुछ रासायनिक पदार्थ थे।

अधिकारियों ने उसे बार-बार आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जैसे-जैसे स्थिति बिगड़ती गई, पुलिस को उसके आक्रामक व्यवहार के जवाब में गोली चलानी पड़ी। इस मुठभेड़ में आर्या को गोली लग गई। उसे तुरंत इलाज के लिए जोगेश्वरी ट्रॉमा अस्पताल ले जाया

गया, जहाँ बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गोलीबारी बच्चों को बचाने की कोशिश के दौरान हुई, जिन्हें परिसर से सुरक्षित निकाल लिया गया। टकराव की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जाँच चल रही है।

घटना तब शुरू हुई जब पुणे निवासी मानसिक रूप से विक्षिप्त रोहित आर्या ने कथित तौर पर एक वेब सीरीज़ के ऑडिशन के बहाने आरए स्टूडियो में 17 बच्चों, एक वरिष्ठ नागरिक और एक अन्य नागरिक को बुलाया। अंदर घुसते ही उसने दरवाज़े बंद कर दिए और समूह को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। पुलिस को दोपहर करीब 1:45 बजे एक आपातकालीन कॉल मिली, जिसके बाद त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) और विशेष इकाइयों ने इमारत को घेर लिया। पहले तो बंधकों को शांतिपूर्वक रिहा कराने के लिए बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन जब बातचीत विफल रही, तो पुलिस बाथरूम के रास्ते स्टूडियो में घुस गई।

एक सावधानीपूर्वक समन्वित अभियान में, पुलिस और अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने 17 बच्चों सहित सभी 19 व्यक्तियों को बचा लिया। बंधकों को स्टूडियो के भूतल पर बंधक पाया गया। पुलिस उपायुक्त दत्ता किशन नलावड़े के अनुसार, बचाए गए सभी लोग सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के पास पहुँच गए हैं। अधिकारी ने पुष्टि की कि जाँच का केंद्र आर्या के इरादों और मानसिक स्थिति का पता लगाना था।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर के बीच चलाएगी एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड-खातीपुरा के फेरे विस्तारित

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारी सीज़न दौरान उनकी यात्रा माँग को पूरा करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस एवं जोधपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा, ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड-खातीपुरा के फेरों को मौजूदा समय, ठहराव और संरचना के अनुसार विस्तारित किया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

1. ट्रेन संख्या 04834/04833 बांद्रा टर्मिनस - जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल (02 फेरे)

ट्रेन संख्या 04834 बांद्रा टर्मिनस - जोधपुर सुपरफास्ट स्पेशल सोमवार, 03 नवम्बर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 11:25 बजे जोधपुर पहुँचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04833 जोधपुर - बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल, रविवार 02 नवम्बर, 2025 को जोधपुर से 06:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 07:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, नागदा, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, वनस्थली निवाई, दुर्गापुरा, जयपुर, आसलपुर जोबनेर, फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09007/09008 वलसाड-खातीपुरा साप्ताहिक स्पेशल के फेरे विस्तारित (02 फेरे) ट्रेन संख्या 09007 वलसाड-खातीपुरा स्पेशल के फेरों को 27 नवम्बर, 2025 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09008 खातीपुरा-वलसाड स्पेशल के फेरों को 28 नवम्बर, 2025 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 04834 और ट्रेन संख्या 09007 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 01 नवम्बर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

गन्ना श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए - उपाध्यक्ष डॉ. नीलम गोरहे

मुंबई। राज्य में गन्ना कटाई का मौसम शुरू हो गया है और गन्ना कटाई करने वालों को तत्काल सहायता प्रदान करना आवश्यक है ताकि बेमौसम बारिश से उन्हें नुकसान न हो। इसलिए, सहकारिता विभाग को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से गन्ना कटाई करने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए, विधान परिषद की उपसभापति डॉ. नीलम गोरहे ने सुझाव दिया।

गन्ना श्रमिकों के प्रस्तावित कल्याण पर चर्चा और भविष्य की दिशा तय करने के लिए विधान भवन में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, कोंकण के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सिद्धराम सलीमथ, उप सचिव अंकुश शिंगाडे, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे, गन्ना प्रसंस्करण निगम के प्रबंध निदेशक रवींद्र गोराने, राज्य परिवार कल्याण कार्यालय पुणे के उप निदेशक डॉ. आशीष भारती उपस्थित थे।

उपाध्यक्ष डॉ. गोरहे ने कहा कि गन्ना श्रमिक राज्य के चीनी उद्योग की रीढ़ हैं। बेमौसम बारिश के कारण वे काफी परेशान हैं और उनकी समस्याओं को देखते हुए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। इसलिए, उन्हें समय पर गमबूट, इलेक्ट्रिक रीपर, सैनिटरी नैपकिन, दस्ताने जैसी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्यम से सहायता प्रदान करना आसान होगा। साथ ही, ग्रामीण विकास विभाग और संबंधित विभाग के माध्यम से मोबाइल शौचालयों की व्यवस्था करने के न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है, उन्होंने इस अवसर पर कहा।

गन्ना श्रमिकों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए उनके कार्यस्थल पर साप्ताहिक मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था की जानी चाहिए और महिला श्रमिकों के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध कराए जाने चाहिए। साथ ही, महिला गन्ना श्रमिकों को मातृत्व अवकाश और मातृत्व योजना का लाभ देने पर भी विचार किया जाना चाहिए, उन्होंने इस अवसर पर कहा। उपाध्यक्ष डॉ. गोरे ने यह भी कहा कि अगली बैठक में गन्ना श्रमिकों के कल्याण पर चर्चा के लिए छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, धाराशिव, अमरावती, अहिल्यानगर, नासिक, सतारा, बुलढाणा, नांदेड़, लातूर, जलगांव, सतारा, सांगली के जिला कलेक्टरों के साथ एक बैठक की योजना बनाई जाएगी।

मध्य रेलवे ने 5.0 के अंतर्गत 'स्वच्छता पखवाड़ा - 2025' विशेष अभियान मनाया

मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने महात्मा गांधी और श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मध्य रेलवे ने विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत 01.10.2025 से 15.10.2025 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा - 2025' अभियान का आयोजन किया। यह अभियान रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों, कार्यालयों, कॉलोनियों, कार्यशालाओं, अस्पतालों, खान-पान की दुकानों आदि सहित सभी स्थानों पर स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया गया था। यह अभियान भारतीय रेलवे द्वारा देश भर के सभी जोनों, मंडलों और कार्यशालाओं में आयोजित स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा है।

मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री विजय कुमार ने 2 अक्टूबर 2025 को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। महाप्रबंधक ने महात्मा गांधी के भित्तिचित्रों और स्वच्छता नारे से सजे ईएमयू रेक्स का निरीक्षण किया और महात्मा

गांधी की तस्वीर और 'स्वच्छता ही सेवा' और 'स्वच्छोत्सव' के संदेश वाले इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों का भी निरीक्षण किया।

उपनगरीय लॉबी में महात्मा गांधी की महानता और उनकी शिक्षाओं का प्रतीक एक आकर्षक रंगोली बनाई गई थी, जो सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करती है।

महाप्रबंधक ने एक ईएमयू रेक में नए समर्पित वरिष्ठ नागरिक डिब्बे का भी निरीक्षण किया। मध्य रेलवे के संपदा कार शेड ने एक बॉम्बार्डियर ईएमयू रेक के एक सामान डिब्बे को वरिष्ठ नागरिक डिब्बे में परिवर्तित कर दिया। यह कार्य माटुंगा वर्कशॉप द्वारा पहले की गई पहल के बाद किया गया, जिसने एक सीमेंस ईएमयू सामान डिब्बे को वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिवर्तित किया था।

महाप्रबंधक ने परेल स्थित सांस्कृतिक अकादमी के कलाकारों द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' विषय पर प्रस्तुत प्रेरक नुक्कड़ नाटक की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

स्वच्छता एवं सामाजिक जागरूकता पर आधारित 'वेस्ट टू आर्ट' प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। पर्यटकों और कर्मचारियों ने विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए गांधी भित्तिचित्र और सेल्फी पॉइंट में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

यात्रियों की भागीदारी बढ़ाने और स्वच्छता की आदतें विकसित करने के लिए, यात्रियों को स्वच्छता प्रतिज्ञा पत्र भी वितरित किए गए।

'स्वच्छता पखवाड़ा - 2025' का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2025 को मध्य रेल के अपर महाप्रबंधक श्री प्रतीक गोस्वामी ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्थित ऐतिहासिक महाप्रबंधक भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर किया।

विशेष अभियान 5.0 के तहत, मध्य रेल ने स्वच्छता और ई-कचरे के नियोजित निपटान पर केंद्रित पहल की है। इस अभियान में संपूर्ण स्वच्छता, बेहतर स्थान प्रबंधन, कार्यस्थलों का सौंदर्यीकरण, पर्यावरण-अनुकूल पहल, हरित प्रथाओं और नेटवर्क में डिजिटलीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। जनभागीदारी, स्टेशनों पर नागरिक फीडबैक को शामिल करने तथा अनावश्यक सामग्री और स्क्रैप का निपटान करके राजस्व को अधिकतम करने पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके माध्यम से मध्य रेल ने स्वच्छता और आधुनिक प्रबंधन मानकों की अवधारणा को संस्थागत बनाने का प्रयास किया है।

भुसावळ वाणिज्य विभाग द्वारा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भुसावळ मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से अक्टूबर माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन करने वाले वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया।

समारोह का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत अग्रवाल ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। इस अवसर पर वाणिज्य विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-26 में के अप्रैल से अक्टूबर माह के दौरान प्राप्त उल्लेखनीय उपलब्धियों तथा राजस्व वृद्धि पर प्रस्तुति दी गई। इन उपलब्धियों का श्रेय वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के अथक परिश्रम और समर्पण को दिया

गया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री पुनीत अग्रवाल ने अपने संबोधन में कर्मचारियों के कार्य की सराहना करते हुए उनके योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कर्मचारियों को भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट सेवा और प्रदर्शन बनाए रखने का आह्वान किया। समारोह में कुल 150 कर्मचारियों और 03 टीमों को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक (तकनीकी) श्री एम. के. मीना, वरिष्ठ शाखा अधिकारी, वाणिज्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

समारोह की प्रस्तावना वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अजय कुमार ने की, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया। कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री बी. बी. तपस्वी ने किया। यह समारोह वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध हुआ, जिससे उन्हें भविष्य में और अधिक उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त हुई।

पश्चिम रेलवे मना रही है सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2025

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

पश्चिम रेलवे पर 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक 'सतर्कताः हमारी साझा ज़िम्मेदारी' विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस जागरूकता सप्ताह का उद्देश्य लोक प्रशासन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है, साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने में कर्मचारियों और जनता की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सप्ताह भर चलने वाले इस आयोजन के अंतर्गत नैतिक आचरण और सुशासन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और जनजागरण गतिविधियाँ आयोजित की गईं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 30 अक्टूबर, 2025 को मुख्यालय कार्यालय, चर्चगेट में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य भाषण मुख्य अतिथि, बॉम्बे उच्च

न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री पृथ्वीराज के. चव्हाण ने दिया।

कार्यक्रम के दौरान श्री चव्हाण द्वारा पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता, अपर महाप्रबंधक श्री प्रदीप कुमार और वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री कुलदीप कुमार जैन के साथ मिलकर 'सतर्कता बुलेटिन - 2025' विमोचन किया गया।

इस कार्यक्रम में पश्चिम रेलवे की सांस्कृतिक टीम द्वारा 'चाय पानी' नामक एक आकर्षक नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें सार्वजनिक सेवा में ईमानदारी और पारदर्शिता के महत्व पर प्रभावी ढंग से प्रकाश डाला गया।

पूरे सप्ताह के दौरान पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों, कारखानों और क्षेत्रीय इकाइयों में विभिन्न गतिविधियाँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि सहभागी सतर्कता को बढ़ावा दिया जा सके और यह संदेश दिया जा सके कि सतर्कता प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है।

आठ साल बाद स्थानीय चुनावों की खर्च सीमा बढ़ी, कहां के उम्मीदवार कितना खर्च कर सकेंगे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने आठ साल बाद स्थानीय निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा में बड़ा संशोधन किया है। आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि अब मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे ए-क्लास नगर निगमों में उम्मीदवार अधिकतम 15 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। यह संशोधन आने वाले निकाय चुनावों के मद्देनजर किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मुंबई, पुणे और नागपुर जो ए-क्लास की श्रेणी में आते हैं। वहां के उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा 15 लाख रुपये तय की गई है। वहीं, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक और ठाणे जैसे बी-क्लास नगर निगमों के लिए यह सीमा 13 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

सी-क्लास नगर निगमों जैसे कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर और वसई-विरार में उम्मीदवार अब 11 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा, शेष 19 डी-क्लास नगर निगमों के लिए नौ

लाख रुपये की सीमा तय की गई है। आयोग के मुताबिक, यह संशोधन 2017 के बाद पहली बार किया गया है।

आयोग ने नगर परिषदों और पंचायतों के लिए भी नई खर्च सीमा तय की है। ए-क्लास नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 15 लाख रुपये और सदस्य के लिए पांच लाख रुपये खर्च की सीमा रखी गई है। बी-क्लास नगर परिषदों में यह सीमा क्रमशः 11.25 लाख और 3.5 लाख रुपये है, जबकि सी-क्लास नगर परिषदों में अध्यक्ष के लिए 7.5 लाख रुपये और सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपये खर्च की अनुमति दी गई है।

ग्राम पंचायत के लिए नई व्यवस्था

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, जिला परिषदों में 71 से 75 सीटों वाले क्षेत्रों में सदस्य पद के लिए खर्च सीमा नौ लाख रुपये रखी गई है, जबकि पंचायत समिति सदस्य के लिए छह लाख रुपये तय की गई है। जिन जिला परिषदों में 61 से 70 सीटें हैं, वहां सदस्य पद के लिए 7.5 लाख रुपये और पंचायत समिति के लिए 5.25 लाख रुपये की सीमा रहेगी।

ग्राम पंचायतों के लिए भी स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई है जिन पंचायतों में सात से नौ सदस्य हैं, वहां सरपंच चुनाव के लिए 75 हजार रुपये और सदस्य के लिए 40 हजार रुपये खर्च की अनुमति है। वहीं, 11 से 13 सदस्यीय पंचायतों में सरपंच 1.5 लाख रुपये और सदस्य 55 हजार रुपये तक खर्च कर सकते हैं। 15 से 17 सदस्यीय पंचायतों के लिए सरपंच की सीमा 2.65 लाख रुपये और सदस्य की 75 हजार रुपये रखी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह संशोधन बढ़ती महंगाई और चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी उम्मीदवारों को इस नई सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।

मध्य रेल

एएलएस एम्बुलेंस की भर्ती

निविदा सूचना सं. GEM/2025/B/6831904

कार्य का विवरण: माटुंगा कार्यशाला कर्मचारियों के लिए टाइप डी, एएलएस (एडवांस लाइफ सपोर्ट) एम्बुलेंस की भर्ती। **मात्रा:** रेट शेड्यूल के अनुसार **निविदा समापन / खोलने और समय की तिथि:** 19.11.2025, 9:00 बजे तक। निविदा विवरण और निविदा दस्तावेज **www.gem.gov.in** वेबसाइट पर उपलब्ध है। निविदाएं वेबसाइट के माध्यम से केवल ई-टेंडरिंग प्रारूप में ही स्वीकार की जाएंगी। उप मुयांअ(I) 606

अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

क्रमांक एचओ/8373/जीटीबी(एसई)/दिनांकः 30.10.2025

ई-निविदा सूचना

निविदा दस्तावेज़ संख्या	बोली संख्या 2025_MCGM_1236537_1
संगठन का नाम	टीबी अस्पताल समूह, सेवरी
विषय	जीटीबी अस्पताल, सेवरी के मुख्य भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित आईआरसीयू में पेंट्री और चेंजिंग रूम का प्रावधान।
निविदा की लागत	1452+ (18.0% जीएसटी)
ई-निविदा की लागत (अनुमानित लागत)	वस्तु दर निविदा
बोली सुरक्षा जमा/ईएमडी	रू 10,000.00
निविदा जारी करने और बिक्री की तिथि	31.10.2025 प्रातः 11:00 बजे से
निविदा बिक्री और बोली सुरक्षा जमा की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय	06.11.2025 सायं 5:00 बजे तक
पैकेट ए और पैकेट बी का उद्घाटन	11.11.2025 प्रातः 11:00 बजे के बाद
संचार का पता	कार्यालयः चिकित्सा अधीक्षक, जीटीबी अस्पताल, जेरबाई वाडिया रोड, सेवरी, मुंबई-400015
बोली खोलने का स्थान	चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में ऑनलाइन।

पीआरओ/2067/विज्ञा./2025-26

चिकित्सा अधीक्षक जीटीबीएच

भोजन से पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ स्वच्छ धोएं।

रा. सु. गवई के कार्यों का सम्मान करते हुए स्मारक और ग्रंथसूची - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

दिवंगत नेता रा. सु. (दादासाहेब) गवई के स्मारक का उद्घाटन

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

सरकार ने स्वर्गीय दादासाहेब गवई के समग्र कार्य-सफ़र का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक स्मारक और एक संदर्भ पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय लिया है, ताकि उनका कार्य एक मार्गदर्शक बने और नई पीढ़ी उनके कार्यों को पहचान सके। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से उनके कार्यों को गौरवान्वित किया है।

राज्य सरकार द्वारा अमरावती में निर्मित दिवंगत नेता रा. सु. गवई के स्मारक का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। यह कार्यक्रम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण गवई की उपस्थिति में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, एडवोकेट. आशीष जायसवाल, न्यायमूर्ति भूषण गवई की माता कमलताई गवई, सांसद डॉ. अनिल बोंडे, बलवंत वानखड़े, विधायक किरण सरनाईक, संजय खोडके, रवि राणा, सुलभा खोडके, प्रताप अडसड, केवलराम काले, प्रवीण तायडे, राजेश वानखड़े, उमेश उर्फ ??चंदू यावलकर, गजानन लवटे, चरणसिंह ठाकुर, चैनसुख संचेती, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिला कलेक्टर

आशीष येरेकर, नगर आयुक्त सौम्या शर्मा-चांडक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आर. सु. गवई के कार्यों के सम्मान में एक स्मारक बनाया गया है। हमारा लक्ष्य है कि इसका उपयोग विश्वविद्यालय के छात्र करें और यह नई पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करे। आने वाले समय में इस क्षेत्र में एक बड़ा सभागार बनाया जाएगा। इसलिए, यह स्मारक युवाओं के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगा। स्मारक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रणाली के माध्यम से आर. सु. गवई के दृश्य-श्रव्य भाषण सुनने को उपलब्ध होंगे। स्मारक को कियोस्क, डिजिटल वॉल आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है।

रा. सु. गवई एक अजातशत्रु थे। उन्होंने समाज की समस्याओं का समाधान करके अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। इसीलिए उनका लंबा राजनीतिक सफर महत्वपूर्ण हो गया है। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उन्होंने जैन और बौद्ध तीर्थस्थलों के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने शैक्षिक सुधारों पर भी ज़ोर दिया। भारतीय संविधान के प्रति उनका गहरा सम्मान था। संविधान संशोधन के बारे में उनका वाक्य, 'मैं इसका पुरज़ोर विरोध करता हूँ', अमर है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उनका मानना ??था कि संविधान के माध्यम से हर मुद्दे का समाधान संभव है।

न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा, रा. सु. गवई के स्मारक का निर्माण पूरा होना एक सपने के साकार होने जैसा है। स्मारक की आधारशिला रखने से लेकर उद्घाटन तक का काम तेज़ी से किया गया। इस संरचना से नागरिकों को लाभ होगा। इस स्मारक का निर्माण इस दृष्टि से किया गया था कि यह विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। स्मारक में जीवन गाथा को चित्रित करने में रचनात्मकता का ध्यान रखा गया है। इसी कारण स्मारक हर दृष्टि से सुंदर बन गया है। समाज के आशीर्वाद से प्रगति हो रही है। आम लोगों की समस्याओं का समाधान कर न्याय दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में झाड़ियों की समस्या का समाधान किया गया है और इससे अनेक स्कूलों, कॉलेजों और नागरिकों की समस्याओं का समाधान हुआ है।

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, 'रा. सु. गवई का व्यक्तित्व बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों से उपजा था। उनमें विनम्रता, नम्रता और शालीनता थी। उनसे मिलने के बाद, आप उनकी ऊर्जा का अनुभव कर सकते थे। उन्होंने आंदोलन को जीवित रखने के लिए काम किया। इसीलिए वे ज़मीनी स्तर के नागरिकों से जुड़े रहे। वे आम आदमी के मुद्दों पर विधानसभा में आवाज़ उठाते देखे गए हैं। दीक्षाभूमि के साथ-साथ, उन्होंने उस राज्य में तीर्थ स्थलों का विकास किया जहाँ वे राज्यपाल थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में भी आमूल-चूल परिवर्तन किए। उन्होंने सामाजिक न्याय योजनाओं को लागू करने का सुझाव दिया। इसलिए, उन्होंने कहा कि उनका स्मारक मानवता के विचारों के साथ बनाया गया है।

आगामी समय में रा. सु. गवई का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने सुझाव दिया कि इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित की जाएँ। स्मारक का कार्य उच्च गुणवत्ता का रहा है। आने वाले समय में स्मारक के विस्तार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा भी उत्कृष्ट रूप से बनाई गई है। दादासाहेब ने अपने कार्यकाल के दौरान सभी के साथ उत्कृष्ट समन्वय स्थापित किया। उनका राजनीतिक सफर विधायक, सांसद और राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल लंबा रहा। उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि उन्होंने उत्कृष्ट वाकपटुता के साथ नेतृत्व और उपलब्धियाँ हासिल कीं।

सरकारी अस्पतालों में मृत्यु दर कम करने के लिए तत्काल उपाय करें- चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में मृत्यु दर कम करने के लिए तत्काल उपाय करने के निर्देश दिए हैं। सेंट जॉर्ज अस्पताल में मृत्यु दर में वृद्धि को गंभीरता से लेते हुए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मुश्रीफ ने इस संबंध में एक तत्काल बैठक आयोजित की। इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव धीरज कुमार, निदेशक डॉ. अजय चंदनवाले, जे.जे. अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल के डीन और चिकित्सा अधीक्षक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में मृत्यु दर कम करने के लिए, अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं में तत्काल सुधार लाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन, धन और उपकरणों की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने गहन चिकित्सा इकाई में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, मानव संसाधन बढ़ाने, दवाइयाँ और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने और दीर्घकालिक सुधार योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए। मुश्रीफ ने कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि आईसीयू में मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि कई मरीज़ों को अंतिम चरण में निजी अस्पतालों से सरकारी अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

2022 और 2025 के बीच समग्र मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। 2022 में 2040 मरीज़ और 2025 में 7407 मरीज़ सफल उपचार के बाद घर लौटे।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की है और एक पारदर्शी जाँच और एक सुदृढ़ सुधार योजना तैयार की है। अस्पताल में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए ठोस उपाय लागू किए जा रहे हैं।

तत्काल उपाय

1. 'आईसीयू' में आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी और महत्वपूर्ण दवाएँ तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश
2. गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सर जे.जे. अस्पताल ले जाने के निर्देश आवश्यकतानुसार सुसज्जित एम्बुलेंस के साथ अस्पताल

1. सेंट जॉर्ज अस्पताल में जनशक्ति, दवाओं का स्टॉक और आईसीयू बेड बढ़ाने के आदेश।
2. मुंबई सहित राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की गहन समीक्षा करके सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मृत्यु दर की मासिक समीक्षा करने का निर्णय।
4. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने यह भी बताया है कि सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि, मानव संसाधन और दवाओं की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

मुंबई में निजी कोचिंग कक्षाओं के निरीक्षण हेतु एक समिति गठित की जाए- विधान परिषद सभापति प्रो. राम शिंदे

15 दिनों के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

बृहन्मुंबई महानगरपालिका को मुंबई शहर में चल रही निजी कोचिंग कक्षाओं के निरीक्षण हेतु सभी संबंधित अधिकारियों की एक समिति गठित करनी चाहिए। यह समिति मुंबई में निजी कोचिंग कक्षाओं का निरीक्षण करे और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करे, विधान परिषद सभापति प्रो. राम शिंदे ने निर्देश दिया।

विधान परिषद सदस्य राजेश राठौड़ द्वारा 2025 के मानसून सत्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को आकर्षित करने के लिए निजी कक्षाओं द्वारा छात्रों से धोखाधड़ी और मुंबई में एलन क्लासेस की कई शाखाओं की उपस्थिति के संबंध में उठाई गई चिंताओं के संबंध में हाल ही में विधान भवन में अध्यक्ष प्रो. राम शिंदे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में स्कूली शिक्षा मंत्री श्री दादाजी भुसे, विधायक श्री राजेश राठौड़, स्कूली शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल सहित शिक्षा विभाग और मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी उपस्थित थे।

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के साथ-साथ राज्य में भी कई निजी कोचिंग कक्षाएं चल रही हैं। कक्षाएं संचालित होने का स्थान, कक्षा स्थल पर अग्नि सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था, छात्रों से अधिक शुल्क लेना और उसमें कम राशि दिखाना, कर चोरी, आवासीय परिसर की अनुमति प्राप्त भवनों में निजी कक्षाएं शुरू करना और अनधिकृत निर्माण, इन सभी की जाँच की जानी चाहिए। साथ ही, संबंधित विभाग छात्रों से ली जाने वाली फीस की भी जाँच करें, ऐसा विधान परिषद के सभापति प्रो. राम शिंदे ने कहा।

बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि राज्य में निजी कोचिंग कक्षाओं के संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। अध्यक्ष प्रो. राम शिंदे ने कहा कि इस विधेयक और संबंधित कानून को पूर्ण बनाने के लिए जनता से भी सुझाव मांगे जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र में निजी कक्षाओं के संबंध में एक सर्वसमावेशी विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कैंसर रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला नगर निगम बनने पर

नवी मुंबई नगर निगम की अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसा

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

नवी मुंबई नगर निगम की ओर से, नेरुल स्थित मासाहब मीनाताई ठाकरे अस्पताल में एक कैंसर रजिस्ट्री विभाग कार्यरत है, जहाँ टीएमसी खारघर स्थित कैंसर महामारी विज्ञान केंद्र (ण्ऊ्रिं) के चिकित्सा अभिलेख एवं कैंसर रजिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर एवं प्रभारी अधिकारी डॉ. अतुल बुदुख के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की डॉ. मैग्डेलेना पचकोन्स्की (निदेशक, कैंसर रजिस्ट्री, वाइटल स्ट्रैटेजीज़, न्यूयॉर्क), डॉ. हाटू काई लिन (देश समन्वयक एवं वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार, जन स्वास्थ्य विभाग, वाइटल स्ट्रैटेजीज़, श्रीलंका), डॉ. अर्पिता पाल (सह निदेशक, वाइटल स्ट्रैटेजीज़, नई दिल्ली) ने निरीक्षण के बाद इस पहल का दौरा किया और इसकी सराहना की। टीम ने नवी मुंबई नगर निगम के पवने स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा और निरीक्षण किया।

इस दौरे के दौरान, नवी मुंबई मनपा की सहायक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धनवंती घाडगे, पैथोलॉजिस्ट डॉ. संगीता बनसोडे ने कैंसर रजिस्ट्री के बारे में

जानकारी देते हुए बताया कि मनपा आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे के मार्गदर्शन में, कैंसर रजिस्ट्री विभाग 11 अक्टूबर, 2024 से मनपा के मॉंसाहेब मीनाताई ठाकरे अस्पताल, नेरुल में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत जावड़े के नियंत्रण में कार्यरत है।

इस विभाग के अंतर्गत नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में रहने वाले कैंसर रोगियों का पंजीकरण किया जाता है। इसके माध्यम से नवी मुंबई मनपा क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या, कैंसर से होने वाली मौतें और किस प्रकार का कैंसर अधिक प्रचलित है, इसकी जानकारी एकत्र की जा रही है। भविष्य में, इस जानकारी का उपयोग कैंसर के बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने के लिए किया जाएगा।

डॉ. मैग्डेलेना पचकोन्स्की और डॉ. अतुल बुदुख ने नवी मुंबई को सभी नगर निगमों में कैंसर रजिस्ट्री शुरू करने वाला पहला नगर निगम और 20 लाख से कम आबादी वाले सरकारी/नगरपालिका निकायों में भी पहला नगर निगम बताते हुए इसकी सराहना की और इस पहल के लिए नवी मुंबई नगर निगम को बधाई दी।

टाटा एक्ट्रेक, नवी मुंबई नगर निगम के लिए कैंसर रोगियों के पंजीकरण हेतु निःशुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराएगा और इसके विशेषज्ञ नवी मुंबई नगर निगम के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही, नवी मुंबई नगर निगम की इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर से धन उपलब्ध कराने की अनुशंसा की जाएगी और नवी मुंबई नगर निगम को कैंसर रजिस्ट्री की अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता प्रदान करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, ऐसा टाटा एक्ट्रेक के प्रभारी अधिकारी डॉ. अतुल बुदुख ने बताया।

भारत का इस्पाती ढाँचा - अखिल भारतीय सेवा और राष्ट्र निर्माण

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

किसी राष्ट्र का मूल्यांकन न केवल उसके भूगोल से होता है, बल्कि उसकी संस्थाओं की दक्षता, निष्पक्षता और लचीलेपन से भी होता है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में, अखिल भारतीय सेवाएँ (आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस) प्रशासन की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती रही हैं, केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करती रही हैं और सरकार व नागरिकों के बीच एक कड़ी प्रदान करती रही हैं। ये सेवाएँ विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित हैं। इस क्षेत्र में किए गए योगदान से पता चलता है कि सरदार वल्लभभाई पटेल का दृष्टिकोण एक मजबूत, एकजुट और उत्तरदायी राष्ट्र के निर्माण का मार्गदर्शन करता रहेगा।

इस्पाती ढाँचे का जन्म

स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की स्थिति को समझते हुए, सरदार वल्लभभाई पटेल ने पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह 'इस्पातीय ढाँचा' है। यह केंद्र को विभिन्न राज्यों से जोड़ेगा, संतुलित नीतियों को लागू करेगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगा। सरदार ने यह स्पष्ट रूप से कहा था। वल्लभभाई पटेल जानते थे कि केवल राजनीतिक एकता ही पर्याप्त नहीं है; मज़बूत संस्थाएँ सिद्धांतों को व्यवहार में लाने और शांति एवं प्रगति को बनाए रखने की नींव थीं।

प्रशासनिक सामंजस्य और स्थिरता

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी देश भर में नीतियों और जनता के बीच एक कुशल कड़ी का काम करते हैं। ज़िलों और राज्यों में कार्यरत, वे चुनाव कराने, सामाजिक कल्याण योजनाओं को लागू करने, कानून के शासन को बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक ज़िले में उनकी उपस्थिति शासन को केवल शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि राष्ट्र निर्माण की यात्रा में प्रत्येक नागरिक को शामिल करती है। कई क्षेत्रों में, अधिकारी आपदा प्रबंधन, स्थानीय नियोजन और सामाजिक पहलों में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं, जो इस 'इस्पात ढाँचे' के बहुआयामी प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

चाहे प्राकृतिक आपदा हो, सामाजिक अशांति हो या महामारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी नीतियों और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतरता, समन्वय और नेतृत्व प्रदान करते हैं। केंद्रीय नीतियों को स्थानीय वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने की उनकी क्षमता भारत को आंतरिक चुनौतियों का सामना करने और विविधता में एकता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। असम में बाढ़ से लेकर गुजरात में भूकंप तक, संकट के समय में उनका नेतृत्व समुदायों को स्थिर रखता है और आवश्यक सेवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

राष्ट्रीय मूल्यों का समावेश

प्रशिक्षण, प्रशासन और नागरिकों के साथ दैनिक संवाद के माध्यम से, अखिल भारतीय सेवाएँ साझा उत्तरदायित्व और राष्ट्रीय उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देती हैं। अधिकारी विविध समूहों के बीच मध्यस्थता करते हैं, विवादों का समाधान करते हैं और समावेशी नीतियों को लागू करते हैं, जिससे शासन में एकता और विश्वास मज़बूत होता है। यह दैनिक कार्य सामाजिक सद्भाव, कानून और न्याय के प्रति सम्मान और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देता है - जो एक संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत मूल्य हैं। अखिल भारतीय सेवा सरदार पटेल के इस विश्वास का जीवंत उदाहरण है। मज़बूत संस्थाएँ एक अखंड भारत की नींव हैं। वे दृष्टि को कार्य में, नीतियों को व्यवहार में और विचारधारा को राष्ट्रीय एकता के ठोस रूपों में परिवर्तित करते हैं।

राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान किसी भी राजनीतिक या सांस्कृतिक प्रयास जितना ही महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि देश के हर कोने में एकता, निष्पक्षता और राष्ट्रीय सेवा के आदर्श जीवित रहें।

पशुपालन व्यवसाय को कृषि के समकक्ष दर्जा मिलने से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी- पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

राज्य सरकार ने पशुपालन को कृषि के समकक्ष दर्जा देने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, बिजली दरों में रियायती लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और इससे पशुपालकों को रियायती बिजली दरों का लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पशुपालन मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में योगदान मिलेगा।

पशु उत्पादों के लिए मूल्य श्रृंखला का निर्माण, कृषि की तरह समूह पशुपालन, आधुनिक तकनीक को अपनाने से स्वतः ही वृद्धि होगी। पशुपालन व्यवसाय के लिए कृषि और अन्य श्रेणियों के बजाय कृषि श्रेणी के अनुसार बिजली शुल्क लेने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार, अब प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। इससे पशुपालन व्यवसाय में लगे पशुपालकों को बिजली दरों में रियायत का लाभ मिलेगा। इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया गया है।

रियायत का लाभ उठाने के लिए, संबंधित पशुपालन परियोजनाओं को जिला उपायुक्त (पशुपालन एवं डेयरी) के पास पंजीकरण कराना होगा। साथ ही, परियोजना में शामिल सभी पशुओं का एनडीएलएम (भारत पशुधन पोर्टल) पर पंजीकरण कराना होगा। पशुपालन परियोजना के लिए अलग से बिजली मीटर होना भी अनिवार्य है। इस रियायत का उपयोग पशु आवास, चारा/पशु आहार, जल पंप, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन मशीनरी के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, बंद परियोजनाएँ और निष्क्रिय सहकारी समितियाँ इस रियायत के लिए पात्र नहीं होंगी।

छूट प्राप्त करने की प्रक्रिया

संबंधित तालुका पशुपालन अधिकारी द्वारा मौजूदा पात्र लाभार्थियों का विवरण महावितरण को उपलब्ध कराया जाएगा। नए लाभार्थियों को बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन जमा करना होगा और उसकी एक प्रति सहायक आयुक्त (पशुपालन एवं डेयरी) को जमा करनी होगी।

तालुका स्तर पर, सहायक आयुक्त (पशुपालन एवं डेयरी) और उप-कार्यपालक अभियंता समन्वयक होंगे, जबकि जिला स्तर पर, उपायुक्त (पशुपालन) और कार्यपालक अभियंता (महावितरण) समन्वय करेंगे। पात्र लाभार्थियों को बिजली शुल्क में रियायत प्रदान करने के लिए महावितरण कंपनी के लिए अलग से विवरण रखना अनिवार्य है।

सभी जिलों से पात्र लाभार्थियों की जानकारी महावितरण द्वारा एकत्रित की जाएगी और आयुक्त (पशुपालन एवं डेयरी), पुणे कार्यालय के माध्यम से मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक), महावितरण, मुंबई को भेजी जाएगी।

नागपुर के पास कार और बस की टक्कर में तीन लोगों की मौत

महाराष्ट्र के नागपुर जिले में बुधवार को एक कार के एक निजी यात्री बस से टकराने में तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर वडम्बा गांव के पास दोपहर में हुई। एक अधिकारी ने बताया, जबलपुर जा रही कार एक दोपहिया वाहन से टकराने से बचने के कारण नियंत्रण

खो बैठी और यात्री बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और उसमें सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

अधिकारी ने बताया कि मृतकों की पहचान जबलपुर निवासी कपिल साहनी (50), अमित अग्रवाल (51) और संदीप सोनी (51) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि हादसे में एक मोटरसाइकिल सवार और उसकी पत्नी, बस चालक और कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आईं। उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा आगे की जांच जारी है।

स्कूल पोषण कर्मियों की मांगों के प्रति सकारात्मक रुख - स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे

मुंबई,। स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल पोषण कर्मियों की लंबित मांगों के प्रति सकारात्मक रुख रखता है और उनके पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संपर्क करेगा।

स्कूल पोषण कर्मियों की लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में, स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल, उप सचिव तुषार महाजन, निदेशक (प्राथमिक) शरद गोसावी, स्कूल पोषण कर्मचारी संघ महासंघ (सीटू) और शिवशक्ति स्कूल पोषण कर्मचारी रसोइया सहायक एवं ठेकेदार संघ के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

स्कूल शिक्षा मंत्री श्री भुसे ने कहा कि स्कूल पोषण कर्मियों के पारिश्रमिक में केंद्र और राज्य सरकारों का हिस्सा होता है। केंद्र सरकार को दिनांक 9 अप्रैल 2025 के पत्र द्वारा केंद्रीय अंशदान में वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है, जिस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी। स्कूल पोषाहार कार्यकर्ताओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, अन्य राज्यों द्वारा लिए गए निर्णयों का अध्ययन कर न्यूनतम वेतन अधिनियम के संबंध में भी मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा।

स्कूल पोषाहार कार्यकर्ताओं को वर्तमान में 2,500 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। 5 जुलाई 2024 की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इन श्रमिकों के वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी लागू की जाए, श्रमिकों के काम के घंटों का रिकॉर्ड रखा जाए और उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जाए, श्रमिकों को 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए, दिवाली भाऊबीज के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान किया जाए, पेंशन लागू की जाए, वर्दी प्रदान की जाए, काम करते समय चोट लगने पर चिकित्सा दावा किया जाए और मृत्यु होने पर वारिसों को 5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए, आदि। इस दौरान रखी गई मांगें इस प्रकार थीं: मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि इन मांगों में से जायज मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।

सम्पादकीय

13, 000 से ज्यादा छात्र आत्महत्याएं पढ़ाई का दबाव या व्यवस्था की नाकामी? कब सुधरेगा तंत्र, कैसे बचेगा भविष्य? सुप्रीम कोर्ट ने मांगा राज्यों से ब्योरा

शिक्षण संस्थानों का वास्तविक अर्थ है, जहां ज्ञानार्जन के साथ-साथ विद्यार्थियों के भीतर व्यावहारिक कौशल और जीवन में चुनौतियों से मुकाबला करने की मानसिक शक्ति भी विकसित होती है। मगर जब कोई विद्यार्थी अपनी जिंदगी से हार मानने को मजबूर हो जाए, तो इन संस्थानों का महत्त्व क्या रह जाता है? क्या आज के शिक्षण संस्थानों का उद्देश्य सिर्फ किताबी ज्ञान बांटना रह गया है?

क्या संस्थानों के प्रबंधन का यह दायित्व नहीं है कि वे अपने परिसर में ऐसा माहौल तैयार करें कि कोई भी विद्यार्थी बिना किसी भेदभाव, परेशानी और तनाव के शिक्षा ग्रहण कर सके? इसी लापरवाही का नतीजा है कि देशभर में विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले साल-दर-साल बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने की गंभीरता कहीं नजर नहीं आती है।

यही कारण है कि अब सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन पर आठ सप्ताह के भीतर विस्तृत ब्योरा पेश करने को कहा है।

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की हाल की एक रपट भी इस बात की तस्दीक करती है कि देश में विद्यार्थियों की आत्महत्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रपट के मुताबिक, वर्ष 2023 में विद्यार्थियों की आत्महत्या के 13, 892 मामले सामने आए, जो वर्ष 2013 की तुलना में लगभग पैंसठ फीसद अधिक है। जबकि वर्ष 2019 की तुलना में यह वृद्धि चौंतीस फीसद दर्ज की गई है। समग्र तौर पर देखें, तो वर्ष 2023 में हुई कुल आत्महत्या में विद्यार्थियों की संख्या आठ फीसद से अधिक थी। यह स्थिति वास्तव में भयावह है। विद्यार्थियों की मानसिक स्थिति बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं।

मसलन, पढ़ाई का दबाव, शिक्षा संस्थानों में हिंसा और जातिगत भेदभाव या फिर घरेलू एवं आर्थिक परेशानियां। ये ऐसी समस्याएं हैं, जिनका समय रहते समाधान किया जा सकता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में 25 जुलाई के अपने फैसले में सरकार और शिक्षा संस्थानों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे।

शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी बेहद संवेदनशील मसला है। सरकार और शिक्षा संस्थानों को विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संकट को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी नियमावली और दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व के फैसले में यह भी निर्देश दिया था कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दो महीने के भीतर तमाम निजी कोचिंग केंद्रों के लिए पंजीकरण, छात्र सुरक्षा मानदंड और शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य करने वाले नियम अधिसूचित करें।

मगर राज्यों की उदासीनता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। इसमें दोराय नहीं कि शैक्षणिक संस्थानों और कोचिंग केंद्रों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की रोकथाम के लिए अब एकीकृत और ठोस नियमावली लागू किए जाने की जरूरत है।

इनके प्रभाव की वार्षिक समीक्षा भी होनी चाहिए और उसी लिहाज से नियमों को अद्यतन किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को किसी भी तरह के मानसिक दबाव से छुटकारा मिल सके।

भारत-कनाडा संबंध : सुधार की दिशा में नई पहल और संभावनाएँ

भारत और कनाडा के बीच संबंध ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुसांस्कृतिक समाज और वैश्विक सहयोग की समान विचारधारा साझा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संबंध राजनीतिक मतभेदों और कुछ विवादास्पद घटनाओं के कारण तनावपूर्ण दौर से गुज़रा। इसका सबसे अधिक प्रभाव उन आम भारतीय नागरिकों, छात्रों और पेशेवरों पर पड़ा जो कनाडा में अपनी शिक्षा और रोजगार के माध्यम से जीवन निर्माण कर रहे हैं। अब जब दोनों देशों के बीच संबंध सुधार की दिशा में नई पहल दिखाई दे रही हैं, तो उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी है।

भारत-कनाडा संबंधों में गिरावट की मुख्य वजह रही कनाडा में सक्रिय राष्ट्र विरोध का मुद्दा। भारत ने लगातार यह चिंता जताई कि कनाडा की भूमि का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इस विषय पर कई बार राजनयिक स्तर पर असहमति और बयानबाजी हुई, जिसने द्विपक्षीय संवाद को प्रभावित किया। स्थिति तब और तनावपूर्ण हुई जब कुछ राजनीतिक समूहों ने कनाडा में देश द्रोही समर्थक प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियां आयोजित कीं। भारत की नजर में यह न केवल उसकी आंतरिक सुरक्षा में हस्तक्षेप था, बल्कि द्विपक्षीय विश्वास को भी कमजोर करने वाला कदम। इन घटनाओं के चलते उच्च-स्तरीय वार्ता ठप पड़ गईं, निवेश और

व्यापारिक समझौतों की गति धीमी हो गई, और शिक्षा-वीज़ा जैसे विषयों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ा। हजारों भारतीय छात्र जो कनाडा में पढ़ाई या नौकरी की तलाश में थे, उन्हें वीज़ा प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

अब हालात धीरे-धीरे बदलते दिखाई दे रहे हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों की सरकारों ने संवाद बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की हैं। द्विपक्षीय वार्ता के पुनः प्रारंभ होने से यह संकेत मिला है कि भारत और कनाडा अब अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग की नई राह पर चलना चाहते हैं।

सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन यह है कि कनाडा सरकार ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया है। आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी और नियंत्रण के संकेत मिले हैं। यह कदम न केवल भारत के हित में है, बल्कि कनाडा के अपने सामाजिक ताने-बाने की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। आतंक किसी भी लोकतंत्र के लिए घातक होता है – और यदि कनाडा इस दिशा में ठोस कार्रवाई करता है, तो यह संबंधों में भरोसे का नया अध्याय खोलेगा।

भारत और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंध लंबे समय से परस्पर लाभकारी रहे हैं। कृषि, तकनीकी, शिक्षा, ऊर्जा और खनन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारतीय आईटी कंपनियां और स्टार्टअप कनाडा में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहे हैं, वहीं कनाडाई कंपनियाँ भारत के विशाल बाजार में निवेश बढ़ा रही हैं। 2023-24 के दौरान राजनीतिक तनाव के चलते व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। कई कंपनियों ने निवेश योजनाएं रोक दीं और दोनों देशों के बीच निर्यात-आयात में गिरावट दर्ज की गई। लेकिन अब सुधार की दिशा में उठाए जा रहे कदम इन अड़चनों को दूर करने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी, निवेश का माहौल बेहतर होगा और नए व्यापारिक समझौते संभव होंगे।

कनाडा भारतीय छात्रों के लिए सबसे पसंदीदा शैक्षणिक गंतव्यों में से एक है। वर्तमान में लगभग तीन लाख से अधिक भारतीय छात्र वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर वर्क वीजा पर कनाडा में कार्यरत हैं। इन छात्रों और कामगारों ने दोनों देशों के बीच न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक पुल भी बनाया है। हालांकि, संबंधों में तनाव के चलते वीज़ा नीतियों और वर्क परमिट की प्रक्रियाओं में कठिनाई आने लगी थी। इससे छात्रों की पढ़ाई और करियर पर असर पड़ा। यदि अब संबंधों में स्थिरता आती है, तो वीज़ा प्रक्रिया सुचारू होगी, शैक्षणिक अवसर बढ़ेंगे, और पेशेवर सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

भारत और कनाडा के बीच मानव संबंधों की जड़ें गहरी हैं। कनाडा में चौदह लाख से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं जो कनाडा के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये प्रवासी समुदाय दोनों देशों के बीच सेतु का काम करता है। जब राजनीतिक माहौल शांत होता है, तो इस प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए अवसर भी बढ़ते हैं और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत होता है। भारत-कनाडा संबंधों का सुधार केवल एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों की साझा आकांक्षा है। स्थिर और सहयोगी संबंध शिक्षा, रोजगार और व्यापार के अवसरों को बढ़ाते हैं, जबकि उग्रवाद और अविश्वास केवल नुकसान पहुंचाते हैं। यदि दोनों देश आपसी सम्मान और सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यह साझेदारी वैश्विक स्तर पर भी एक आदर्श उदाहरण बन सकती है। आगामी वर्षों में उम्मीद की जा सकती है कि भारत और कनाडा आतंकवाद के विरुद्ध साझा नीति अपनाएँगे, व्यापारिक समझौतों को नई गति देंगे और शिक्षा व तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे।

भारत-कनाडा संबंधों का सुधार एक सकारात्मक संकेत है, जो केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि छात्रों, कामगारों, निवेशकों और आम नागरिकों के जीवन में भी स्थिरता, अवसर और विकास लेकर आएगा। यदि कनाडा खालिस्तानी तत्वों पर ठोस कार्रवाई कर, भारत की चिंताओं को दूर करता है, तो यह न केवल राजनीतिक तनाव कम करेगा बल्कि विश्वास, सहयोग और साझेदारी के नए युग की शुरुआत भी करेगा।

जब मन के शब्द कागज पर उतरकर बनते थे यादें 'लाइक्स' की दुनिया में छूट गई डायरी लिखने की आदत

डायरी मात्र कागज के पन्नों का संग्रह नहीं है। यह आत्मा का एकांतवास है, जहां मन की अव्यक्त पीड़ा, अनकहे सपने और जीवन के क्षणिक उजाले बिना किसी संकोच के उतर आते थे। वह दौर अब अतीत की धुंध में खो रहा है, जब रात्रि की निस्तब्धता में किसी कलम की सरसराहट उस हृदय की धड़कन बन जाती थी, जो दिनभर के शोरगुल में गुम हो गई थी। डायरी लिखना एक अनुष्ठान था, स्वयं से संवाद स्थापित करने की एक पवित्र क्रिया। यह एक ऐसा दर्पण था, जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविक छवि देखता था, जिसमें कोई मुखौटा नहीं होता था। सोशल मीडिया के इस युग में, जहां सब कुछ सार्वजनिक है, डायरी की वह अंतरंगता, वह व्यक्तिगत 'निजता' एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। हम अपनी भावनाओं को 'लाइक' और 'कमेंट' की कसौटी पर तौलने लगे हैं, जिसके कारण डायरी का वह कोना, जहां निस्वार्थ भाव से जीवन स्वयं को लिखता था, आज धूल फांक रहा है।

डायरी विधा का लुप्त होना केवल एक साहित्यिक हानि नहीं है, बल्कि यह मानव मन के गहन आत्म निरीक्षण की प्रक्रिया पर लगा एक विराम चिह्न है। डायरी हमें सिखाती थी कि कैसे हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करें, गलतियों से सीखें और छोटी-छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। डिजिटल स्क्रीन की चकाचौंध में हम अपने अंदर झांकने का अभ्यास खो रहे हैं। डायरी के पन्नों में समय ठहर जाता था, वह पल अमर हो जाता था। वह कलम की स्याही केवल शब्द नहीं लिखती थी, बल्कि वह आंसुओं और मुस्कानों का लेखा-जोखा होती थी। महान लेखकों, विचारकों और यहां तक कि आम लोगों की डायरियां इतिहास के सबसे प्रामाणिक दस्तावेज हैं।

ऐन फ्रैंक की डायरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने युद्ध की विभीषिका में भी मानवता की लौ को जलता रखा। क्या आज सोशल मीडिया पर लगातार 'ताजा' या अद्यतन रहना उस गहराई और उस मार्मिकता को छू सकते हैं? नहीं। बल्कि इससे होता यह है कि सोशल मीडिया हमारे सोचने-समझने के दायरे को सीमित कर देता है और हमारी संवेदनाएं भी उसे से प्रभावित और संचालित होने लगती हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर सोचने-समझने की प्रक्रिया सीमित या स्थगित होती है, तो उसके बाद वास्तव में हमारा बौद्धिक विकास भी रुक जाता है। फिर हमारे सामने जिस भी बात, प्रचार, धारणा को रखा जाता है, हम उसे उसी नजरिए से देखने लगते हैं, जिसकी हमसे मांग होती है।

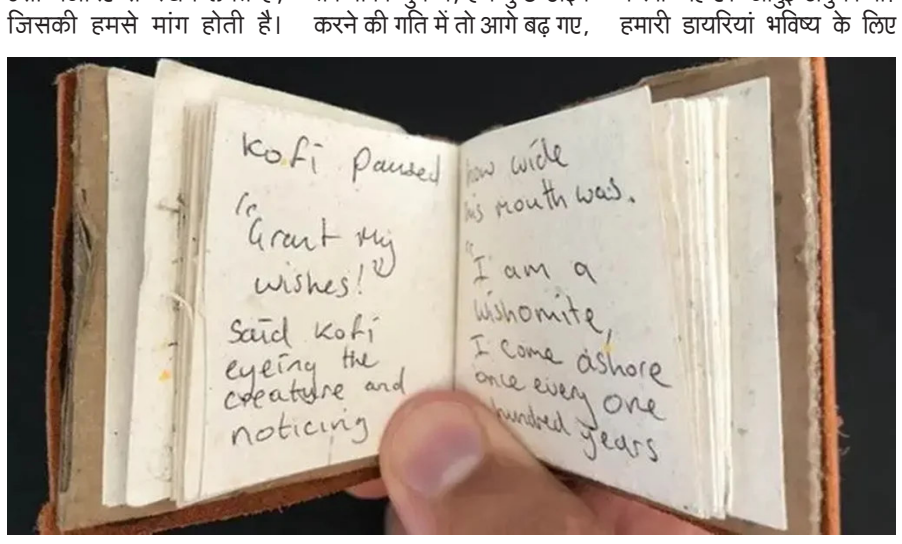

प्रकारांतर से देखा जाए, तो वहां हमारी सोच पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती।

जीवन में जब कोई बड़ा तूफान आता था, तो डायरी के पन्ने ही थे, जो 'सांत्वना' का एक अदृश्य हाथ थामते थे। यह विधा हमें 'अल्प विराम' लेने का महत्त्व समझाती थी, जब जीवन की दौड़ में गति इतनी तीव्र हो जाती थी कि हम अपनी सांसें लेना भूल जाते थे। सोशल मीडिया पर सब कुछ तत्काल और क्षणिक है, जबकि डायरी धीर और स्थायी थी। वह हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती थी। इस तकनीकी युग में, हम कुछ टाइप करने की गति में तो आगे बढ़ गए, पर हस्तलेखन यानी हाथ से लिखने की आत्मा को पीछे छोड़ दिया। हर लिखावट में एक अनूठी ऊर्जा होती थी, एक व्यक्तित्व की छाप, जो आज के डिजिटल अक्षरों में गुम हो गई है। आधुनिक तकनीक ने डायरी के स्वरूप को बदलने का प्रयास किया है, 'ब्लाग लिखना' या 'डिजिटल पत्रकारिता' के रूप में, पर वह हाथ से लिखने का सुख, भौतिक जुड़ाव कहां! जब हम कलम को कागज पर रगड़ते थे, तब विचारों को एक मूर्त रूप मिलता था। वह स्याही की गंध, पन्नों का पलटना, सालों बाद उन पन्नों को छूकर अतीत को फिर से महसूस करना- यह एक 'जादुई' अनुभव था। हमारी डायरियां भविष्य के लिए पुरातत्त्व थीं, जो हमारे व्यक्तिगत इतिहास को सहेजती थीं।

डायरी लेखन वास्तव में एक चिंतनशील प्रक्रिया थी, जो हमारी मानसिक शांति के लिए एक 'थेरेपी' या इलाज का काम करती थी। यह हमें अपने भीतर के उलझे हुए धागों को सुलझाने का अवसर देती थी। किसी प्रियजन के खोने का दुख हो, या करियर में आई कोई बाधा, डायरी वह अश्रुपूर्ण कंधा थी, जिस पर हम बिना किसी डर के अपना सिर रख सकते थे। आज के दौर में, जब मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चिंता बन गया है, डायरी की यह उपचार शक्ति अत्यंत महत्त्वपूर्ण थी। यह एक प्रकार का 'आत्म-निकासी' थी। सोशल मीडिया पर जब हम अपनी 'सफलता' का प्रदर्शन करते हैं, तब डायरी हमें हमारी मानवता याद दिलाती थी। डायरी का खोना, हमारे सत्य से हमारा विमुख होना है। अहं को पोषित करने वाली इस दुनिया में, डायरी ही थी, जो हमें 'मैं कौन हूं', इसका ईमानदारी से जवाब देती थी।

अपने जीवन में कई ऐसे मौके आते थे, जब हम दुनिया से खुद को छिपाना चाहते थे, लेकिन खुद से नहीं। इसी खुद को अपने सामने खड़ा करके उसे सब कुछ बताने, उससे सवाल पूछने, कठघरे में खड़ा करने या किसी खास मामले में खुद को शाबासी देने का सहारा बनती थी हमारी डायरी। डायरी तो एक 'गुरु' थी, जो हमें 'ध्यान' की कला सिखाती थी, विचारों को स्थिर करने की युक्ति बताती थी। दुनिया की आपाधापी में अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के क्रम में हम चाहे जितनी अस्थिरता से गुजरें, लेकिन ठीक उसी वक्त हम स्थिर रहने के भूखे भी होते थे। डायरी हमारे मन को वही स्थिरता देती थी।

युद्ध और शांति के हर किस्से में, महिलाएं सिर्फ पात्र नहीं निर्माता हैं - बस इतिहास ने उन्हें याद नहीं रखा

युद्ध की विभीषिका में जब बारूद की गंध हवा में घुलती है, तब सबसे पहले खामोश हो जाती है किसी मां की लोरी, बेटी की हंसी और महिलाओं की सुरक्षा का भरोसा। यही वह क्षण है, जब यह सवाल सबसे गहरा लगता है कि शांति की राह में महिलाएं कहां हैं? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस की ओर से विश्व में संघर्षों को लेकर उठाया गया मसला महज औपचारिक चिंता नहीं, बल्कि उस सच्चाई का प्रतिरूप है जो दुनिया के हर कोने में महिलाओं के अनुभवों में दर्ज है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि आज वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च बढ़ रहा है, सशस्त्र संघर्षों की संख्या पहले से अधिक है तथा इन सबके बीच महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा भयावह रूप ले चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महिला एजंसी के अनुसार, इस समय लगभग 67.6 करोड़ महिलाएं घातक संघर्षों के पचास किलोमीटर के दायरे में रह रही हैं। यह संख्या वर्ष 1990 के दशक के बाद से सबसे अधिक है। यह आंकड़ा केवल एक सांख्यिकीय सूचना नहीं, बल्कि शांति के प्रयासों में हमारी सामूहिक विफलता का प्रमाण है।

विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की रपट बताती है कि जहां भी किसी देश ने शांति वार्ताओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की, वहां युद्धविराम औसतन पैंतीस फीसद अधिक समय तक कायम रहा। फिर भी आज केवल तेरह फीसद शांति समझौतों में ही महिलाओं की प्रत्यक्ष भूमिका दर्ज की जाती है। यह वैश्विक असंतुलन केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं है, बल्कि मानवीय समझ के संकट का संकेत है। क्योंकि जहां महिलाएं निर्णय में अनुपस्थित होती हैं, वहां शांति भी अधूरी रह जाती है। महिलाएं युद्ध के दौरान केवल पीड़िता नहीं होतीं, वे जीवन, पुनर्निर्माण और सामंजस्य की वाहक होती हैं। लेकिन जब दुनिया के बड़े मंचों पर युद्ध और कूटनीति की बातें होती हैं, तब उनकी आवाज किसी कोने में दब जाती है। मानो यह दुनिया केवल हथियारों और सत्ता की भाषा ही समझती हो।

भारत के संदर्भ में यह सवाल और भी जटिल है। यहां नारी को देवी के रूप में पूजने की परंपरा रही है, लेकिन सत्ता, नीति और निर्णय लेने में उसकी भागीदारी आज भी सीमित है। पंचायतों में आरक्षण ने महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का अवसर दिया, लेकिन राष्ट्रीय नीति-निर्माण, सुरक्षा परिषदों और शांति वार्ताओं में उनकी संख्या नाममात्र की है। भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी केवल चौदह फीसद के आसपास है, जो वैश्विक औसत छब्बीस फीसद से काफी कम है।

यह तब है, जब भारत उन देशों में शामिल है जहां महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सामाजिक सुधारों तक हर मोर्चे पर अग्रणी भूमिका निभाई है। झांसी की रानी, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, सावित्रीबाई फुले, या आज की इरोम शर्मिला। इन सभी ने यह साबित किया कि महिला जब नेतृत्व करती है, तो संघर्ष भी करुणा में बदल सकता है। मगर आज भी निर्णय लेने वाले मंचों पर उनकी उपस्थिति अपवाद है, नियम या परंपरा नहीं।

दुनिया भर में शांति निर्माण की प्रक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि जब महिलाएं किसी संघर्ष के समाधान में शामिल होती हैं, तो वे मुद्दों को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, सामाजिक पुनर्गठन के स्तर पर भी देखती हैं। वे परिवार और समाज के उस ताने-बाने को समझती हैं, जो युद्ध की विभीषिका में टूट कर बिखर जाता है। उदाहरण के लिए- लाइबेरिया की शांति प्रक्रिया में महिलाओं के नेतृत्व ने वर्षों से चले आ रहे गृहयुद्ध का अंत किया। लेयमा गबोवी और उनकी साथियों ने शांति के लिए ऐसा आंदोलन चलाया, जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि बिना हथियारों के भी युद्ध समाप्त हो सकता है।

बोस्निया, कोलंबिया और फिलीपींस में भी महिला मध्यस्थों ने शांति समझौतों को स्थायित्व दिया। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर वर्ष 2023 तक किसी भी बड़ी अंतरराष्ट्रीय वार्ता में महिलाओं की भागीदारी पंद्रह फीसद से आगे नहीं बढ़ पाई। यह स्थिति केवल लैंगिक असमानता नहीं, बल्कि सामूहिक विवेक की विफलता है। संयुक्त राष्ट्र महिला एजंसी के ताजा आंकड़े बताते हैं कि आज दुनिया में हर दस में से एक महिला किसी न किसी प्रकार की हिंसा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में यह अनुपात और भयावह है। सीरिया, सूडान, यूक्रेन, गाजा, कांगो जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है।

हर संघर्ष के बाद जब इतिहास 'शांति' के नाम पर समझौते लिखता है, तब वह उन लाखों महिलाओं की पीड़ा को दरकिनार कर देता है, जिनके शरीर और मन पर युद्ध के घाव दर्ज होते हैं। और जब पुनर्निर्माण का दौर आता है, तो वही महिलाएं घरों, बच्चों, समाज और भविष्य को फिर से जोड़ने का काम करती हैं। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि जिनके कंधों पर पुनर्निर्माण का भार है, उन्हें निर्णय के मंच पर स्थान ही नहीं मिल पाता। भारत की सामाजिक वास्तविकता भी किसी संघर्ष क्षेत्र से कम नहीं। यहां हिंसा के स्वरूप बदल गए हैं। कभी घरेलू हिंसा, कभी झूठी शान के लिए हिंसा, कभी कार्यस्थलों पर शोषण तो कभी राजनीतिक बहिष्कार। समाज के भीतर जो असमानता पलती है, वह धीरे-धीरे उस बड़े संघर्ष में बदल जाती है, जो किसी सीमा या धर्म से बंधा नहीं होता। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक स्थायित्व की शर्त बन जाती है।

जब कोई महिला पंचायत में निर्णय लेती है, तो वह किसी सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व करती है। जब वह न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरती है, तो केवल अपने अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि वह समाज की दिशा तय करती है। शांति का अर्थ केवल युद्धविराम नहीं है, बल्कि यह भय से मुक्ति, न्याय की उपस्थिति और समानता का अनुभव है। लेकिन शांति की इस परिभाषा को गढ़ने का अवसर अब भी पुरुष-प्रधान व्यवस्था ने अपने पास रखा है। जब तक शांति को 'सुरक्षा नीति' और 'सैन्य रणनीति' के दायरे में सीमित रखा जाएगा, तब तक यह अधूरी ही रहेगी। क्योंकि वास्तविक शांति केवल हथियार डाल देने से नहीं आती, वह तब आती है जब समाज की चेतना हिंसा के विचार को अस्वीकार कर देती है। और यह चेतना महिलाओं के भीतर जन्मजात होती है। वे जानती हैं कि युद्ध की कीमत सिर्फ सैनिकों की जान नहीं, बल्कि पीढ़ियों का भविष्य चुकाता है। भारत को भी इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।

आज जब हम 'नारी शक्ति वंदन' की बातें करते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि क्या हमारे नीति-निर्माण, कूटनीति और सुरक्षा मंचों पर महिलाओं की आवाज सचमुच सुनी जा रही है। क्या शांति, विकास और न्याय के विमर्शों में महिलाओं की राय को शामिल किया जा रहा है? यह प्रश्न केवल लैंगिक समानता से जुड़ा नही है, बल्कि मानवीय स्थायित्व का है। शांति की सबसे गहरी परिभाषा वही महिला लिखती है, जो सब कुछ खोकर भी जीवन से उम्मीद नहीं छोड़ती है। जब वह राख के बीच से आशा की नई किरण खोजती है, तो वही मानवता का पुनर्जन्म होता है। इसलिए, दुनिया अगर सचमुच शांति चाहती है, तो उसे महिलाओं को दर्शक नहीं, सहभागी बनाना होगा। क्योंकि अंततः शांति किसी संधि पर लिखे गए शब्दों से नहीं आती, वह एक महिला के हृदय से निकलती है, जो बारूद की गंध के बीच भी जीवन की खुशबू तलाश लेती है।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिला स्वास्थ्य समिति, शासी निकाय की मासिक समीक्षा बैठक

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी शैलेष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्टेट्रट सभागार में सम्पन्न हुआ।

स्वास्थ्य विभाग के हर कार्यक्रम की कंपोजिट रिपोर्ट अगले बैठक में प्रस्तुत किया जाए। सभी एमओआईसी आशा व एएनएम की हफ्ते में बैठक कर सघन समीक्षा करने का निर्देश दिया। यूनिसेफ, यूएनडीपी की तरह समस्त एमओआईसी अपने ब्लॉकों में जाकर स्थलीय विजिट कर अवलोकन करें। मातृत्व दर का सही डेटा प्रस्तुत किया जाए। सीएचसी, पीएचसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देते हुए खराब स्थिति को ठीक करने का निर्देश दिया।

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 संतोष कुमार चक ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं व क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति से जिलाधिकारी को अवगत कराया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत आयुष्मान आरोग्य मन्दिर में लैब स्लैब एवं बेसिंग उपलब्धता पर बल

दिया। स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डॉक्टरों के उपस्थिति की चेकिंग एवं कार्य के प्रति उनकी दक्षता का सतत् मूल्यांकन हो। एंटी स्नेक वैक्सीन की सभी पीएचसी, सीएससी पर उपलब्धता सुनिश्चित हो। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में व्यक्तिगत व टीम बेस्ड इंटेंसिव बढ़ाने व सुधार करने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। सभी पीएचसी , सीएचसी पर ड्यूटीरूम सहित सभी जगह साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने बायोमेडिकल बेस्टेज को सही तरीके से निस्तारित किये जाने पर जोर दिया। साथ ही आरबीएसके के कार्य संचालन हेतु कार्यरत मोबाइल हेल्थ टीमों को स्कूलों में जॉच हेतु जाने के लिए वाहनों की उपलब्ध को सुनिश्चित करने पर बल दिया।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने सभी एमओआईसी को निर्देशित किया कि संस्थागत प्रसव को बढ़ाये, इस सन्दर्भ में आशा व एएनएम को प्रेरित करें। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता/दृष्टि दोष की जॉच हेतु जिलाधिकारी ने कैम्प लगाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया। ई-कवच समरी रिपोर्ट के अन्तर्गत जिलाधिकारी ने सभी एमओआईसी को आभा आईडी जनरेट करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जनपद में कार्यरत सभी कम्युनिटी आफिसर को निर्देशित किया कि आयुष्मान आरोग्य मन्दिर की प्रभावी क्रियाशीलता हेतु अटेन्डेंस के माध्यम से नियमित करें, लापरवाही न बरते। सभी आयुष्मान आरोग्य मन्दिर पर बिजली, पानी, दवा की उपलब्धता शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो। जहॉ कुछ कमी है, वहॉ के चिकित्सा अधीक्षक, डीपीआरओ व सीडीओ से समन्वय स्थापित कर पूर्ण कराये। जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा करते हुए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया कि सभी अपने उत्तरदायित्वों व कार्यो का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें।

दो दिवसीय जनपद स्तरीय खेलकूद एवं संस्कृतिक प्रतियोगिता का हुआ समापन

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। स्पोर्ट्स स्टेडियम मूसीलाटपुर के ग्राउंड में दो दिवसीय 27वी जनपद स्तरीय खेलकूद एवं संस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक औराई दीना नाथ भास्कर एवं विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान जी रहे। उच्च प्राथमिक विद्यालय ज्ञानपुर देहात की बालिकाओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही विकास चौधरी एवं संचालन बीएल पाल एवं जया त्रिपाठी द्वारा किया गया। 50 मीटर दौड़ में दीपक प्रथम अर्श कनौजिया द्वितीय सागर भोजवाल तृतीय रहे।100 मीटर में हर्ष कनौजिया प्रथम दीपक द्वितीय और अमन पुरी तृतीय रहे। इसी तरह से 200 मीटर की दौड़ में अमन पुरी प्रथम शिवम यादव द्वितीय एवं दिनेश

कुमार प्रीति रहे। इसी तरह से 400 मीटर दौड़ में अमनपुरी प्रथम सत्यम द्वितीय शिवम यादव तृतीय रहे। लंबी कूद में दीपक प्रथम गौरव पाल द्वितीय और सत्यम तृतीय रहे । खो खो प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय असनाव विजेता रहा। बालिका वर्ग में 50 मीटर दौड़ में खुशी उपाध्याय प्रथम शिवानी द्वितीय साक्षी तृतीय रही। 100 मीटर दौड़ में खुशी उपाध्याय प्रथम शिवानी द्वितीय साधना प्रजापति तृतीय। इसी तरह से 200 मीटर दौड़ में शिवानी प्रथम आंचल यादव द्वितीय मही गुप्ता तृतीय रहे। 400 मीटर दौड़ में आंचल यादव प्रथम शिवानी द्वितीय अर्पिता तृतीय रही। इस अवसर पर जिला व्यायाम शिक्षक मनोज कुमार उपाध्याय जिला स्काउट मास्टर समरजीत यादव दिलीप सिंह सुधीर कुमार सिंह धीरेंद्र यादव अरुण अखिलेश कुमार यादव मानिकचंद यादव अरुण दुबे डीपी चक्रवर्ती आलोक श्रीवास्तव अरुण यति प्रतीक मालवीय सूर्यकांत मौर्य योगेंद्र बहादुर सिंह सभाजीत डॉ परविंदर यादव शिवम श्रीवास्तव राजेंद्र यादव खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह यशवंत कुमार सिंह अशोक कुमार गुप्ता ज्योति योगिता हेमकर अनीता देवी पूजा मिश्रा संजय कुशवाहा अखिलेश मौर्या राजकमल यादव अशोक कुमार मिश्रा डॉ ओम प्रकाश मिश्रा रेखा रानी सहित भारी संख्या में शिक्षक एवं छात्र मौजूद रहे।

डीएम व एसपी द्वारा जिला कारागार का किया गया संयुक्त निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिलाधिकारी शैलेष कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार ज्ञानपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होने जेल में बन्द कैदियों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की भी जानकारी ली, तथा जेल अधीक्षक को सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं को समय से बन्दियों को मुहैया कराने का निर्देश दिया। इस दौरान ज्ञानपुर जिला जेल में निरुद्ध जनपद भदोही के पुरुष/महिला बैरकों में जाकर सरकार द्वारा उन्हें दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने रसोई घर, स्टोर खाद्यान, महिला बैरक/पुरुष बैरक/किशोर बैरक, के निरीक्षण के साथ ही जेल कैम्पस में ही संचालित डिस्पेन्सरी का भी निरीक्षण किया तथा डिस्पेन्सरी में मौजूद दवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। रसोई घर में बन रही आलू परवल की सब्जी, अरहर की दाल, सरसों तेल की गुणवत्ता का भी परीक्षण किया।तत्पश्चात सभी अधिकारियों ने महिला बैरक में पहुच कर उन्हें जेल प्रशासन द्वारा मुहैया करायी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की।

जिलाधिकारी ने कारागार अधीक्षक अभिषेक सिंह को निर्देशित किया कि तैयार कालीनों पर जिला कारागार का अपना लोगों व मार्क भी लगाये, जिससे इन कालीनों की ब्रान्डिग के तहत अगल से पहचान हो सके, तैयार हो रहे भोजन व खाद्य पदार्थो के गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरकों मे पुरूष/महिला कैदी बन्दी है। उपर्युक्त लोगों ने पेयजल व्यवस्था, शौचालय, साफ-सफाई आदि का निरीक्षण के साथ ही मुलाकाती पंजिका का भी अवलोकन किया।

धनुष लीला व सीता स्वयंवर का भव्य मंचन

‘जय श्रीराम’ के नारों से गूंज उठा चौरी बाजार का रामलीला मैदान

मंत्र भारत संवाददाता

चौरी बाजार। प्रगति परिषद द्वारा आयोजित ऐतिहासिक रामलीला के 70वें वर्ष के अवसर पर मंगलवार की शाम धनुष लीला एवं सीता स्वयंवर का मनोहारी मंचन किया गया। जैसे ही श्रीराम स्वरूप ने शिवधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, पूरा मैदान ‘जय श्रीराम’ के नारों और करताल ध्वनि से गूंज उठा। दर्शकों में उत्साह और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला।

इस अवसर पर नगर के कई गणमान्य नागरिक, प्रगति परिषद के पदाधिकारी एवं सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे।

धनुष यज्ञ के पश्चात माता सीता द्वारा श्रीराम को वरण करने का दृश्य अत्यंत भावनात्मक रहा। इसके बाद पवित्र विवाह संस्कार संपन्न हुआ, जिसमें पुष्पवृष्टि और पारंपरिक संगीत ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

मंच की आकर्षक सजावट, प्रकाश व्यवस्था और कलाकारों का जीवंत अभिनय दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि ‘यह रामलीला हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, इसे आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है।’

मिशन शक्ति फेज 5.0 : महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से चलाया गया जागरूकता अभियान

जनपद भदोही में मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को किया गया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। पुलिस अधीक्षक भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल जनपद भदोही के पर्यवेक्षण में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से जनपद के सभी थानों द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इस अभियान के अंतर्गत सभी थानों की एंटीरोमियो टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर जाकर बालिकाओं, महिलाओं एवं आमजन को मिशन शक्ति 5.0

अभियान के तहत जानकारी दी गई, साथ ही महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम व उनके अधिकारों की रक्षा एवं आत्मरक्षा के उपायों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई । कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों को महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चिकित्सा सहायता 108, बाल सहायता नंबर 1098, साइबर हेल्पलाइन 1930 तथा cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी देकर इन सेवाओं के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया । कार्यक्रम के दौरान समस्त थानों पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम द्वारा मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही टेंप्लेट भी वितरित किए गए।

ग्रामीण युवाओं के लिए सुनहरा अवसर : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 10 लाख तक ऋण

गाँवों में बढ़ेगा रोजगार, मिलेगी आर्थिक उड़ान 30 नवम्बर तक करें ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना से बनें स्वरोजगार के भागीदार, अब गांवों में भी खुलेगा उद्योग का रास्ता

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यू पी सिंह ने बताया कि उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण क्षेत्रों में नये उद्योग स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित किया जाता है।

उक्त योजना में अधिकतम धनराशि 10.00 लाख तक के ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराने का प्राविधान है, जिसमें बैंको से प्राप्त ऋण पर एवं उद्योग स्थापित करने पर सामान्य जाति के पुरूष वर्ग को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 'पूँजीगत मद' में 4इ ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा, उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में दिया जायेगा एवं आरक्षित वर्ग (पिछडी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अनु0जाति, अनु0जन जाति, दिव्यांगजन एवं समस्त वर्ग की महिलाओं) को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 'पूँजीगत मंद' में समस्त ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में दिया जायेगा।

उक्त योजना में सामान्य वर्ग के पुरूष को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होगा एवं समस्त आरक्षित वर्ग को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का अशंदान लगाना होगा इच्छुक लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो 'मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना' की बेवसाइट upkvib.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन 30 नवंबर 2025 तक कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन करते समय अपना फोटो, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्थापित कार्यस्थल के ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र (चौहद्दी), प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कर पूर्ण आवेदन की छायाप्रति जिला ग्रामोद्योग अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, रमनगरा सिंहपुर ज्ञानपुर, भदोही में किसी भी कार्य दिवस पर सम्पर्क किया जा सकता है।

21 नवम्बर को मेगा सामूहिक विवाह समारोह–पात्र जोड़ों को मिलेगा ?1 लाख का लाभ, ऑनलाइन आवेदन शुरू

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जिला समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद भदोही में समस्त नागरिकों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह का कार्यक्रम जिलाधिकारी शैलेष कुमार के निर्देशानुसार मेगा-इवेन्ट के रूप में दिनांक 21 नवम्बर 2025 को वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। चल वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जनपद का लक्ष्य 416 निर्धारित किया गया है, जिसका लक्ष्य विकासखण्डवार / नगर पंचायत/नगर पालिका परिषदवार समस्त खण्ड विकास अधिकारी / अधिशासी अधिकारी को आवंटित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आर्थिक रूप से गरीब अभिभावक जो अपनी पुत्री की शादी उक्त सामूहिक शादी कार्यक्रम में सम्पन्न कराना चाहते

है, वे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आनलाइन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/applicationforms.php पर भरते हुये आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट आवश्यक संलग्नको (यथा कन्या के आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र, गरीबी रेखा / निराश्रित / बी0पी0एल0 कार्ड अथवा रू0 3.00 लाख वार्षिक आय सीमा तक का आय प्रमाण-पत्र, कन्या एवं वर की पासपोर्ट साईज फोटो, विधवा होने की स्थिति में पूर्व पति के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति, परित्यक्ता होने की स्थिति में न्यायालय आदेश की प्रति एवं कन्या के बैंक खाता की प्रति) सहित विकासखण्ड मुख्यालय (ग्रामीण क्षेत्र) अधिशासी अधिकारी नगर निकाय (शहरी क्षेत्र) में जमा करना सुनिश्चित करें, पात्र आवेदको द्वारा ही वैवाहिक कार्यक्रम हेतु आवेदन किया जाय। सत्यापन के दौरान यदि कोई भी आवेदक अपात्र पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा। ताकि पात्र व्यक्तियों की कन्याओं की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्पन्न करायी जा सके। योजनान्तर्गत कुल अनुमन्य धनराशि रू0 1.00 लाख (रूपया एक लाख मात्र) के सापेक्ष शादी हेतु रू0 60000/-की धनराशि वधू के बैंक खातें में अन्तरित करायी जायेगी, साथ ही रू0 25000/- तक की उपहार सामग्री का वितरण किया जायेगा एवं रू0 15000/- की धनराशि से उक्त सामूहिक विवाह समारोह को सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम आयोजक को उपलब्ध करायी जानी है।

जिले में शुरू होगा विशेष पुनरीक्षण अभियानः डीएम

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार ने निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों संग बैठक ली। निर्वाचक नामावलियों राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की और उन्हें कार्यक्रम की जानकारी दिए। भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के द्वितीय चरण में देश के 12 राज्यों में विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। इस दौरान डीएम बताए कि यह पुनरीक्षण आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों और समय-सारणी के अनुसार आयोजित किया जाएगा। इस विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समस्त पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हों। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेष कुमार ने बताया की प्रदेश में इसके पहले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही है। जिले में मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। जिला निवार्चन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम 28 से तीन नवम्बर तक विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। चार नवंबर से चार दिसंबर तक बीएलओ बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जाएगा। नौ दिसम्बर को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किए जाने की अवधि नौ दिसम्बर से आठ जनवरी तक होगी। नोटिस जारी किऐ जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि नौ दिसम्बर से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। सात फरवरी को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हों।

नये आपराधिक कानून के सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार के क्रम में प्रभावी क्रियान्वयन के लिये 03 दिवसीय ऱ्ण्ध्‌ जागरूकता अभियान

थानों पर नए व पुराने कानून के तहत कार्यवाहियों के तुलनात्मक चार्ट व विभिन्न पोस्टर के माध्यम से भी किया जा रहा है जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा नये आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0 के सम्बन्ध में 01 जुलाई, 2024 से भारत में नये आपराधिक कानून लागू किये जा चुके हैं, इसके सम्बन्ध में प्रचार-प्रसार के क्रम में नये आपराधिक कानूनों के और प्रभावी क्रियान्वयन के लिये दिनांकः 30-10-2025 से 01-11-2025 तक 03 दिवसीय ऱ्ण्ध्‌ जागरूकता अभियान 2.0 चलाया जा रहा है। जागरूकता कार्यक्रम अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों यथा स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालयों आदि में अधिक से अधिक जन भागीदारी के साथ कराया जा रहा है। नये आपराधिक कानूनों की विशेषतायें, जैसेः- जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण के प्राविधान, नये अपराध, प्रोद्योगिकी और फोरेंसिक के उपयोग से संबंधित प्राविधान, पीड़ित-केन्द्रित प्राविधान, आदि पर जागरूकता कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रकाश डाला जा रहा है।

अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही एवं शुभम अग्रवाल, अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता अभियान 2.0 का उद्देश्य आम जनता को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) जैसे नए कानूनों के बारे में जागरूक करना है। यह अभियान मुख्य रूप से 1 जुलाई, 2024 से लागू होने वाले इन नए कानूनों के प्रावधानों/कार्यवाहियों और उनके महत्व को समझाने के लिए आयोजित किया गया है, ताकि नागरिकों को कानूनी बदलावों की जानकारी हो सके। अभियान के तहत, पुलिस स्टेशनों के प्रभारी अधिकारी द्वारा विभिन्न समुदायों और संस्थानों के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका उद्देश्य नागरिकों को नए कानूनों की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराना है। महिलाओं, युवाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता पैदा करना। इन कानूनों की चर्चा और समझ के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।

वर्तमान कानूनी मुद्दों के बारे में लोगों को शिक्षित करना। प्रत्येक थाना प्रभारी द्वारा अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, प्रमुख हस्तियों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों/कॉलेजों के सदस्य शामिल हुए। यह अभियान भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पर केंद्रित किया गया, जो 01 जुलाई, 2024 से लागू हुए हैं। कार्यक्रम को क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधि आदि के द्वारा काफी सराहा गया एवं भदोही पुलिस की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की गई। पुलिस द्वारा जनता को आश्वस्त किया गया कि नए कानून प्रावधानों के अनुसार जनता को सुरक्षा एवं न्याय दिलाया जा रहा है। चमन सिंह चावड़ा क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर व प्रभारी निरीक्षक ज्ञानपुर द्वारा के एन पी जी कॉलेज ज्ञानपुर, राजीव कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन ज्ञानपुर द्वारा डॉ एन वी एस स्कूल खमरिया थाना औराई जनपद भदोही एवं प्रभारी निरीक्षक चौरी राजेश प्रताप सिंह द्वारा पुलिस टीम के साथ आर.एन.एस पब्लिक स्कूल चौरी जागरूकता अभियान चलाया गया।

दिनांक 01.07.2024 से लागू 03 नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक युग के कानूनों से एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है जो सामाजिक गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। नए कानून दण्ड आधारित न होकर न्याय आधारित है।

तहव्वुर राणा को लेकर खुलेंगे नए राज, जांच आगे बढ़ाने के लिए एनआईए ने यूएस से मांगी कई जानकारियां

मुंबई(संवाददाता)

मंत्र न्यूज

मुंबई। भारत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से नई जानकारियां मांगी हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले में अमेरिका के साथ म्युचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (एमएलएटी) के तहत औपचारिक अनुरोध भेजा है। यह कदम राणा से पूछताछ में मिले नए सुरागों के बाद उठाया गया है। माना जा रहा इन जानकारियों के आने के बाद तहव्वुर राणा से कई राज उगलवाए जा सकते हैं।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने इस्राइल, ब्रिटेन और अमेरिका के नागरिकों की मौत से जुड़े इस हमले की जांच के सिलसिले में अमेरिका से ताजा जानकारी मांगी है। यह संचार तय प्रक्रिया के तहत अधिकृत चैनलों के जरिए किया गया है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया राणा से पूछताछ के दौरान जो नई बातें सामने आई हैं, उनके आधार पर अमेरिका से एमएलएटी प्रक्रिया के तहत और दस्तावेज व जानकारियां मांगी गई हैं।

भारत में तिहाड़ जेल में बंद है तहव्वुर राणा

पाकिस्तान मूल के कनाडाई व्यापारी राणा वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसे 10 अप्रैल 2024 को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था। प्रत्यर्पण से पहले वह अमेरिका के लॉस एंजिलिस स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में न्यायिक हिरासत में था। प्रत्यर्पण प्रक्रिया भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत पूरी की गई थी। राणा ने कानूनी अड़चनें डालने की कई कोशिशें कीं, लेकिन अंततः उसके सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद उसे भारत लाया गया।

एनआईए की जांच में खुलासा हुआ कि राणा ने 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के साथ मिलकर यह हमला प्लान किया था। जांच एजेंसी को दोनों के बीच बड़ी संख्या में फोन कॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक बातचीत के सबूत मिले हैं। हेडली इस समय अमेरिका की जेल में सजा काट रहा है। राणा पर आरोप है कि उसने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहादी इस्लामी जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ मिलकर साजिश रची थी।

26 नवंबर 2008 की रात 10 पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई में घुसे थे। उन्होंने शहर के कई इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिनमें छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और यहूदी केंद्र नरीमन हाउस शामिल थे। इस हमले में कुल 166 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें अमेरिकी, ब्रिटिश और इस्राइली नागरिक भी थे। राणा पर इन्हीं हमलों की योजना बनाने और हेडली को समर्थन देने का आरोप है।

इंडोर स्टेडियम में अनियमितताओं का आरोप

मानवाधिकार संगठन ने की जांच की मांग

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के भिवंडी शहर अध्यक्ष मोमिन दिलशाद अहमद ने भिवंडी महानगरपालिका के आयुक्त को एक पत्र प्रेषित कर इंडोर स्टेडियम में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है।

संस्था द्वारा जारी पत्र के अनुसार, भिवंडी महानगरपालिका की प्रभाग समिति क्रमांक चार के अंतर्गत स्थित स्व. परशुराम टावरे स्टेडियम में बना इंडोर स्टेडियम लंबे समय से बंद है। संस्था का कहना है कि स्टेडियम बंद होने के बावजूद कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बताया गया कि 29 अक्टूबर 2025 को रात्रि लगभग आठ बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि स्टेडियम आधिकारिक रूप से बंद था। मोमिन दिलशाद अहमद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि प्रकरण की विस्तृत जांच कर दोषियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए तथा कार्रवाई की जानकारी संस्था को प्रदान की जाए। संस्था का आरोप है कि इंडोर स्टेडियम के ताले तोड़कर या बिना अनुमति उपयोग करने की घटनाएं गंभीर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती हैं। इस मामले में महानगरपालिका के अधिकारियों की निष्क्रियता पर भी प्रश्नचिह्न लगाया गया है। पत्र के अंत में मोमिन दिलशाद अहमद ने यह चेतावनी दी है कि यदि इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो मानवाधिकार संस्था इस मुद्दे को उच्च स्तर पर उठाएगी। इस संबंध में जब प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त गिरीष घोष्टेकर संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया की पालिका के आर्थिक उत्पन्न के उद्देश्य से स्टेडियम के बगल वाला ग्राउंड एक शादी समारोह हेतु भांडे पर दिया गया था। किन्तु बेमौसम हो रही बारिश के कारण कुछ लोग बरसात से बचने के लिए स्टेडियम का रूख किया। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। जिसकी जांच की जा रही है।

बिजली बिल जमा न होने के विरोध में सड़क पर महिला ने काटा हंगामा, वीडियो वायरल

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के आजमगढ़ जिले के घोसी स्थानीय तहसील एवं वितरण खंड घोसी के नदवासराय से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक महिला ने बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगा कर बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गई है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता महिला वायरल वीडियो में कह रही है कि उसने तीन हजार रुपए बिजली का बिल संविदा कर्मी को दिया था उसके बाद भी उसका बिल जमा नहीं किया गया। महिला का आरोप है कि उसने कई बार बिजली बिभाग के ऑफिस के चक्कर काट चुकी लेकिन उसकी कही पर सुनवाई नहीं हो रही थी।

भिवंडी में म्हाडा कॉलोनी सब्जी मार्केट के अतिक्रमण पर चला मनपा का बुलडोजर

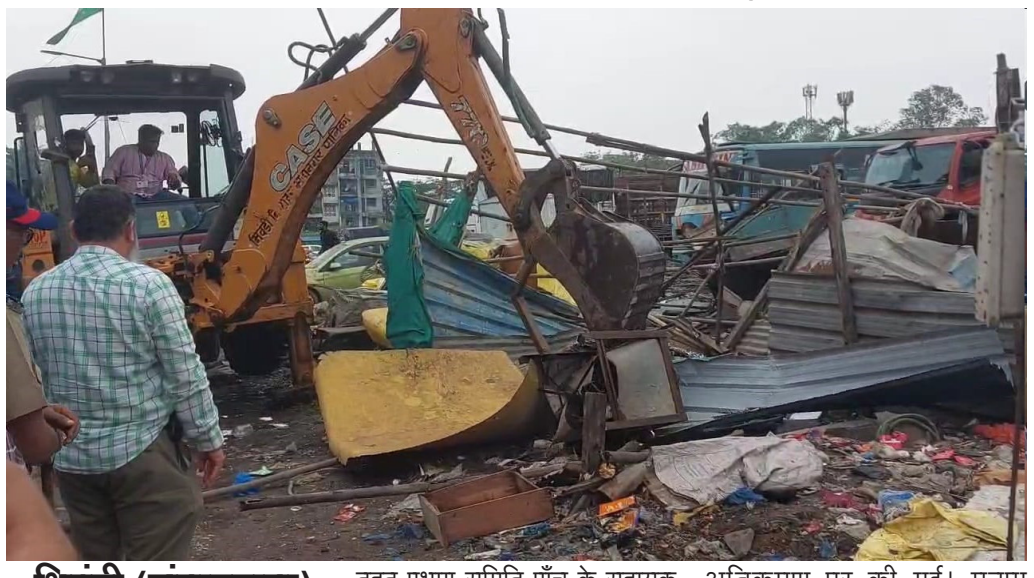

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

भिवंडी शहर में अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के लिए आयुक्त अनमोल सागर , अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल डाके व उपायुक्त अतिक्रमण विक्रम दराडे के निर्देशों के बाद कड़ा रुख अख्तियार की है।जिसके तहत प्रभाग समिति पाँच के सहायक आयुक्त सईद चिवणे, बीट निरीक्षक हनुमान म्हात्रे और मोमिन मुलताझिम के नेतृत्व में अतिक्रमण दस्ते ने स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी में म्हाडा कालोनी स्थित सब्जी मार्केट मे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है।

यह कार्रवाई सिटी सर्वे क्रमांक 10 पर आरक्षित भूखंड पर किए गए अतिक्रमण पर की गई। मनपा अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध कब्जे को हटाया।इस कार्रवाई के दौरान, आरक्षित भूखंड पर अवैध रूप से स्थापित दुकानें और अन्य अतिक्रमण हटा दिए गए हैं।आयुक्त अनमोल सागर ने जानकारी दी है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बिना किसी नरमी के यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

ठाणे जिले के पीडब्ल्यूडी विभाग में करोड़ों के घोटाले का आरोप, कांग्रेस नेता ने मांगी जांच

भिवंडी (संवाददाता)

मंत्र न्यूज

ठाणे जिले के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी (आईएनसी) ठाणे ग्रामीण कांग्रेस के महासचिव पंकज अशोक गायकवाड़ ने विभाग के उप अभियंता दत्तू गीते पर लगभग 200 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच और निलंबन की मांग की है।गायकवाड़ ने जिलाधिकारी को भेजे गए अपने पत्र में लिखा है कि दत्तू गीते पिछले दो दशकों से ठाणे जिले के विभिन्न प्रोजेक्टों में कार्यरत हैं और भिवंडी तालुका क्षेत्र में उन्होंने पीडब्ल्यूडी के कार्यों में भारी अनियमितताएं की हैं। कांग्रेस नेता के अनुसार, अर्नाला-अंबाडी-शिल मार्ग पर किमी 34/650 से 44/150 तक के विशेष दुरुस्ती कार्य के लिए लगभग 4.65 करोड़ की मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना में गीते ने ठेकेदार मयूर

कंस्ट्रक्शन सहित अन्य कंपनियों के साथ मिलीभगत कर 1.65 करोड़ की फर्जी बिलिंग की।गायकवाड़ ने अपने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि 'इगल इंफ्रा कंपनी' नामक ठेकेदार फर्म के माध्यम से लगभग 200 करोड़ रुपये की बोगस बिलिंग की गई है। उन्होंने सवाल उठाया है कि 'ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को विरार-अलीबाग हाईवे प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी आखिर क्यों सौंपी गई?'गायकवाड़ ने जिलाधिकारी से मांग की है कि दत्तू गीते को तत्काल उनके पद से हटाया जाए और उनके खिलाफ उच्चस्तरीय जांच प्रारंभ की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर पूर्व में कई बार लिखित शिकायतें की गईं तथा मीडिया में भी मामले को लेकर रिपोर्टें प्रकाशित हुईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन जल्द कदम नहीं उठाता, तो कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यापक जन आंदोलन छेड़ेगी।

अतिक्रमण पर चला सीईओ तनु जैन का बुलडोजर

सरकारी जमीन पर लोगों ने कर रखा था कब्जा

लखनऊ **(एजेंसी)**। अवैध निर्माण, अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों के विरुद्ध योगी सरकार के आदेश पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी बरेली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तनु जैन, आईडीईएस के निर्देशन में, छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण, अतिक्रमण तथा अवैध कब्जों के विरुद्ध तीन दिवसीय विशेष अभियान आरंभ किया गया। नोटिस के बाद भी कब्जेदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया । इस पर कैंट बोर्ड का बुलडोजर गरजा। सरकारी जमीनों पर बने मकानों के हिस्सों को तोड़ दिया गया। अस्थायी अतिक्रमण हटा दिया गया ।

दअरसल, कैंट के सदर बाजार स्थित मदारी की पुलिया के यादव मोहल्ले में सरकारी जमीन अवैध तरीके से कब्जा करके मकान बयान गया था, जिस को बुलडोजर ध्वस्त किया गया। कैंट बोर्ड की ओर से कार्रवाई शुरू की गई। जिससे लोगों में खलबली मच गई। कई घंटे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली। इस दौरान अस्थायी अतिक्रमण भी हटाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।

बता दें कि बीते दिनों बैंक बोर्ड ने अवैध कब्जेदारों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इसके बावजूद लोगों ने कब्जा नहीं हटाया था। इस पर कैंट बोर्ड का बुलडोजर गरजा तो खलबली मच गई। कुतुबखाना पुल के नीचे नगर निगम की टीम ने हटवाया अतिक्रमण नगर निगम के प्रवर्तन दल ने बुधवार को कुतुबखाना पुल के नीचे दो घंटे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया। मौके पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

प्रवर्तन दल के प्रभारी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि पुल के नीचे फड़ और ठेले लगाने से आवागमन बाधित होने की शिकायत आई थी। इसके बाद टीम वहां पहुंची। टीम ने कब्जे हटाए तो तमाम फड़ व ठेले वालों ने अपना सामान खुद समेट लिया, जो नहीं समेट सके उनका सामान जब्त किया गया है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तनु जैन ने कहा कि 'छावनी परिषद का लक्ष्य नागरिकों के लिए स्वच्छ, व्यवस्थित और सुगम सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिषद का यह अभियान नागरिक सहयोग से ही सफल होगा।

'अपराधी को 20 गोली मारकर लाती है, 1 लिखवाती है'

सीएचसी के डॉक्टर का आरोप- एसपी खड़े होके बनवाते रिपोर्ट, अब सच्चाई आई सामने

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के शामली जिले में में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के चिकित्साधीक्षक डॉ. दीपक कुमार ने ऐसा बयान दिया है, जिससे बवाल मचा हुआ है। उनके बयान से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठता है।

दरअसल, उन्होंने पुलिस पर 'फेक एनकाउंटर' के आरोप जड़ दिए। एक डॉक्टर का ऐसा आरोप जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे पर सावल खड़ा होना शुरू हो गया। नौबत ये आ गई कि पुलिस को सफाई पेश करनी पड़ी। . पुलिस ने अपने बयान में डॉ. दीपक कुमार के दावे की पोल खोल दी जिसके बाद डॉक्टर ने पूर्व में दिए गए अपने बयान को एडिटेड और फेक बताया।

आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले डॉ. दीपक कुमार के कैंप कार्यालय से साढ़े पांच लाख रुपये की चोरी हुई थी। खुलासा न होने पर स्वास्थ्यकर्मियों ने बीते बुधवार को पुलिस के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया। शहर कोतवाली में हंगामे के दौरान डॉ. दीपक इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने पुलिस मुठभेड़ों पर गंभीर आरोप लगा दिए।

कैमरे में कैद एक वायरल बयान में डॉ. कुमार का कथित दावा सामने आया कि 'पुलिस खुद आरोपी को 20 गोलियां मारकर लाती है, लेकिन

सीओ और एसपी खड़े होकर रिपोर्ट में सिर्फ एक गोली दर्ज करवाते हैं।' उन्होंने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि 'हम इनके राज खोलेंगे, मानवाधिकार आयोग से जांच कराई जाए।' डॉ. कुमार के इस बयान ने पुलिस विभाग में हलचल मचा दी।

हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डॉ. कुमार ने सफाई देते हुए इसे फर्जी करार दिया। उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर कहा, 'यह वीडियो पूरी तरह फेक है, किसी ने मेरी जानकारी के बिना रिकॉर्ड कर लिया।' डॉ. कुमार ने दावा किया कि वर्ष 2025 के किसी भी एनकाउंटर के पोस्टमार्टम में वे शामिल नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने स्वास्थ्य-लिवर, हार्ट और मानसिक तनाव-का हवाला देते हुए कहा कि किसी ने 'अनजाने में उनसे कुछ बुलवा लिया, ' जिसका वे खंडन करते हैं।

पुलिस के डर से युवक ने उठा लिया खौफनाक कदम

घर में मचा कोहराम, आरोपी सिपाहियों पर गिरी गाज

शाहजहांपुर **(एजेंसी)**। जिले में नदी के किनारे जुआ खेल रहे जुआरियों के पुलिस को देखते ही नदी में कूदने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है । पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नदी में कूदे पांच अन्य व्यक्ति बच गए । इस मामले में तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बुधवार रात, घटना के सिलसिले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर कोतवाली थाना के सिपाही पंकज कुमार, राजेश कुमार तथा अमन को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ ही मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी (सदर) प्रियंक जैन को सौंप गई है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को बताया कि थाना कोतवाली अंतर्गत खन्नौत नदी के किनारे बुधवार शाम कुछ लोग जुआ खेल रहे थे तभी उधर से एक मामले की जांच के लिए पुलिस गुजरी। द्विवेदी के अनुसार, जुआ खेल रहे लोगों ने पुलिस देखकर समझा कि पुलिस उन्हें पकड़ने आ रही है और घबरा कर छह लोग नदी में कूद गए ।

उन्होंने बताया कि पानी कम होने के कारण पांच लोग नदी से निकल कर भाग गए, परंतु कोविद तिवारी (28) नामक एक अन्य व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि तिवारी जुआरियों को कथित रूप से रुपए देने गया था, वह जुआ नही खेल रहा था लेकिन जुआरियों को भाग कर नदी में कूदते देख उसने भी यही किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शव मिलने के बाद मृतक के परिजन उसे अस्पताल ले गए जहां तिवारी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केरूगंज मार्ग पर मृतक के परिजनों ने जाम लगा दिया। पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और और उन्हें बताया कि तीन सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है इसके बाद जाम खोला गया।

भिवंडी में किसानों की फसलें बेमौसम बारिश से बर्बाद

एपीएमसी ने की 'ओला दुष्काळ' घोषित करने की मांग

भिवंडी। भिवंडी तालुका में इस वर्ष मानसून के समाप्त होने के बावजूद अक्टूबर माह में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बेमौसम बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गईं, जबकि कई किसानों की कटाई के बाद रखी गई फसलें भी भीगकर सड़ गईं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है।

इसी गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भिवंडी कृषि उत्पादन बाजार समिति (एपीएमसी) की ओर से तहसीलदार अभिजीत खोले को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें भिवंडी तालुका को 'ओला दुष्काल' (अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न आपदा) घोषित करने की मांग की गई है।

ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधिमंडल में एपीएमसी के निदेशक श्रीराम पाटील, विशेषज्ञ निदेशक दीपक पाटील, मनोहर ठाकरे और सचिव प्रवीण गायकवाड़ शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से आग्रह किया कि बेमौसम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वेक्षण (पंचनामा) कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा राशि तत्काल प्रदान की जाए।कृषि उत्पादन बाजार समिति के सदस्यों ने बताया कि कई किसानों की महीनों की मेहनत एक ही झटके में बर्बाद हो गई है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं, जबकि कुछ स्थानों पर कटाई के बाद रखी फसलें पूरी तरह सड़ चुकी हैं। किसानों के पास अब बीज, चारा और पुनर्बुवाई के लिए संसाधन भी नहीं बचे हैं।समिति ने सरकार से तत्काल राहत कार्य शुरू करने, फसल बीमा योजनाओं के तहत त्वरित दावा निपटान करने और प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की अपील की है।

ट्रेनिंग के दौरान हादसा, 17 साल के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की मौत, टी20 मैच की तैयारी कर रहा था युवा खिलाड़ी

मेलबर्न **(एजेंसी)**। मेलबर्न के 17 साल के क्लब क्रिकेटर बेन ऑस्टिन की मंगलवार को ट्रेनिंग के दौरान गर्दन पर गेंद लगने से दुखद मौत हो गई। मेलबर्न के बाहरी पूर्वी इलाके में फर्न्ट्री गली में हुई इस घटना के बाद बेन को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वह नेट्स में बल्लेबाजी कर रहे थे। टी20 मैच की तैयारी के लिए साइडआर्म से गेंदें फेंकी जा रही थीं, जिसे 'वैंगर' भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन उसमें स्टेम गार्ड नहीं था। बेन अपने साथियों के साथ टी20 मैच से पहले नेट्स में गेंदों से प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उन्हें चोट लगी। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव केयर पैरामेडिक्स बेन को मोनाश चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल ले गए, जहां बुधवार को उनकी मौत हो गई। फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब ने गुरुवार को उनकी मौत की घोषणा की।

क्लब ने एक बयान में कहा, 'हम बेन की मौत से बहुत दुखी हैं, और उनकी मौत का असर हमारे पूरे क्रिकेट समुदाय पर पड़ेगा। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार जेस, ट्रेसी, कूपर और जैक, उनके बड़े परिवार, उनके दोस्तों और उन सभी के साथ हैं जो बेन को जानते थे और उस खुशी को जानते थे जो वह लाते थे।'

क्रिकेट विक्टोरिया ने बेन के पिता जेस ऑस्टिन और ऑस्टिन परिवार की ओर से एक बयान जारी किया जिसमें लिखा था, 'हम अपने प्यारे बेन की मौत से बहुत दुखी हैं, जिनकी गुरुवार सुबह मौत हो गई। ट्रेसी और मेरे लिए बेन एक प्यारा बेटा था, कूपर और जैक का बहुत प्यारा भाई था और हमारे परिवार और दोस्तों की जिंदगी में एक चमकती रोशनी था। इस दुखद घटना ने बेन को हमसे छीन लिया, लेकिन हमें इस बात का थोड़ा सुकून है कि वह कुछ ऐसा कर रहा था जो वह कई गर्मियों से कर रहा था - दोस्तों के साथ नेट्स में जाकर क्रिकेट खेलना।'

उन्होंने कहा, 'उसे क्रिकेट बहुत पसंद था और यह उसकी जिंदगी की खुशियों में से एक थी। हम उनके टीममेट को भी सपोर्ट करना चाहेंगे जो नेट्स में बॉलिंग कर रहे थे, इस एक्सीडेंट से दो युवा लड़कों पर असर पड़ा है और हमारी दुआएं उनके और उनके परिवार के साथ भी हैं। हम मंगलवार शाम से सपोर्ट के लिए फर्न्ट्री गली क्रिकेट क्लब, मुलग्रेव क्रिकेट क्लब और एल्डन पार्क क्रिकेट क्लब सहित क्रिकेट कम्युनिटी और उन दर्जनों लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो बेन से हॉस्पिटल में मिलने आए। आखिर में, हम घटनास्थल पर मौजूद सभी फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स और मोनाश चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल के स्टाफ को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने बेन की मदद के लिए बहुत मेहनत की। हम बेन को हमेशा याद रखेंगे।'

अर्शदीप सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20आई में भी बाहर बैठना पड़ सकता है : पार्थिव पटेल

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल का मानना है कि तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20आई में भी प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है। पहले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था, और पटेल का मानना है कि टीम प्रबंधन की मौजूदा रणनीति और संतुलन को देखते हुए, मेलबर्न में होने वाले दूसरे मुकाबले में भी उनकी वापसी मुश्किल लगती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अर्शदीप की काबिलियत और संभावनाओं को देखते हुए, टीम भविष्य में उन्हें वापसी का मौका जरूर देगी।

पहले टी20आई में भारतीय टीम ने जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा और शिवम दुबे के साथ गेंदबाजी आक्रमण को चुना था। अर्शदीप, जिन्होंने वनडे सीरीज में हिस्सा लिया और शुरुआती दो मैचों में तीन विकेट झटके थे, को आराम दिया गया। पार्थिव पटेल का कहना है कि टीम मैनेजमेंट फिलहाल दो रिस्ट स्पिनर्स को शामिल करने और निचले क्रम में बल्लेबाजी गहराई बनाए रखने पर जोर दे रही है।

उन्होंने कहा, 'टीम का फोकस अब बैलेंस पर है, जहां गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ी शामिल किए जाएं। हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी इस भूमिका को अच्छे से निभा रहे हैं, इसलिए अर्शदीप को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है।'

26 वर्षीय पंजाब के तेज गेंदबाज़ ने पिछले कुछ महीनों में भारत के लिए कई अहम मैच खेले हैं और डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर डिलीवरी टीम की खास ताकत रही है। फिर भी, हाल के प्रदर्शन और परिस्थितियों के कारण उन्हें फिलहाल रोटेशन स्ट्रेटेजी के तहत टीम से बाहर रखा गया है। पटेल ने कहा, 'टीम थिंक टैंक निश्चित रूप से अर्शदीप को आने वाले मैचों में फिट करने का तरीका खोजेगा। लेकिन फिलहाल, मेलबर्न में दूसरे टी20आई के लिए उनका चयन मुश्किल दिखता है।'

पार्थिव पटेल ने पहले मैच में भारत के प्रदर्शन को लेकर कई सकारात्मक पहलुओं की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग साझेदारी टीम के लिए

उत्साहजनक रही। हालांकि अभिषेक जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनका आक्रामक रवैया और आत्मविश्वास ऑस्ट्रेलिया में उनके पहले दौरे पर भी नजर आया। पटेल ने बताया, 'अभिषेक का नेचुरल गेम खेलना और शुरुआती ओवरों में अटैक करना दिखाता है कि वे घबराए नहीं, बल्कि टीम की रणनीति पर भरोसा रख रहे हैं।' कप्तान सूर्यकुमार यादव की पारी को पार्थिव ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव बताया। उन्होंने कहा कि सूर्या के पारंपरिक फ्लिक्स, स्कूप्स और बैक-फुट शॉट्स देखने से साफ है कि वे अपने पुराने फॉर्म में लौट रहे हैं। पटेल ने कहा, 'बारिश से प्रभावित छोटे मैच में भी सूर्या और शुभमन का स्ट्राइक-रेट शानदार रहा। यह दिखाता है कि दोनों बल्लेबाज़ किसी भी परिस्थिति में टीम को तेज़ शुरुआत देने की क्षमता रखते हैं।'

हॉकी चंडीगढ़ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया-करन गिल्होत्रा

चंडीगढ़ **(एजेंसी)**। भारत में हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हॉकी चंडीगढ़ द्वारा आगामी 7 नवंबर को भव्य भारतीय हॉकी शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि होंगे। हॉकी चंडीगढ़ के अध्यक्ष करन गिल्होत्रा, उपाध्यक्ष अनिल वोहरा और एडवाइजर शालीन कपूर ने श्री कटारिया से मुलाकात कर उन्हें समारोह में आमंत्रित किया। राज्यपाल ने इस आयोजन के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि चंडीगढ़ इस अवसर पर हॉकी के इतिहास में एक नई पहचान बनाएगा। करन गिल्होत्रा ने बताया कि समारोह के आयोजन में चंडीगढ़ प्रशासन, स्पोर्ट्स विभाग और नगर निगम चंडीगढ़ का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा, 'हॉकी भारत की गौरवशाली धरोहर है। 1925 में राष्ट्रीय हॉकी संस्था के गठन से शुरू हुई यह यात्रा आज 100 वर्ष पूरे कर रही है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि चंडीगढ़ इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनेगा। हमारा उद्देश्य नई पीढ़ी को हॉकी के स्वर्णिम इतिहास से जोड़ना है।'

अनिल वोहरा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी, जिसमें तीन प्रदर्शनी मैच खेले जाएंगे, लड़कों के जूनियर और सीनियर वर्गों के मुकाबले तथा लड़कियों का एक विशेष मैच शामिल होगा। इस मौके पर देश-विदेश से हॉकी के कई दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें ओलिंपियन दीपक ठाकुर, राजपाल सिंह, बलजीत सिंह, साथ ही भारत की मौजूदा टीम के कप्तान संजय, मनिंदर सिंह, विक्रमजीत सिंह, और जूनियर टीम के कप्तान रोहित प्रमुख हैं। करन गिल्होत्रा ने आगे बताया कि हॉकी इंडिया के नेतृत्व में देशभर में एक साथ ऐसे शताब्दी समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिससे हॉकी को नया आयाम और नई पहचान मिलेगी।

केनरा बैंक का जुलाई-सितंबर तिमाही में मुनाफा 19 फीसदी बढ़कर 4, 774 करोड़ रुपए

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक का जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 19 प्रतिशत बढ़कर 4, 774 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का पिछले वर्ष की इसी तिमाही में मुनाफा 4, 015 करोड़ रुपए रहा था। केनरा बैंक ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय सालाना आधार पर 34, 721 करोड़ रुपए से बढ़कर 38, 598 करोड़ रुपए हो गई। ब्याज आय सालाना आधार पर 29, 740 करोड़ रुपए से बढ़कर 31, 544 करोड़ रुपए हो गई।

जुलाई-सितंबर तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय घटकर 9, 141 करोड़ रुपए रह गई, जबकि एक साल पहले यह 9, 315 करोड़ रुपए थी। परिचालन आय भी बढ़कर 8, 588 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 7, 654 करोड़ रुपए थी। परिसंपत्ति गुणवत्ता के संदर्भ में बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सितंबर, 2025 के अंत में सकल अग्रिम के 2.35 प्रतिशत तक कम हो गईं, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि तक यह 3.73 प्रतिशत थीं। इसी प्रकार शुद्ध एनपीए या खराब ऋण सितंबर, 2025 के अंत में घटकर 0.54 प्रतिशत हो गया, जबकि सितंबर, 2024 के अंत में यह 0.98 प्रतिशत था।

आलोच्य तिमाही में प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 30 सितंबर, 2025 तक बढ़कर 93.59 प्रतिशत हो गया। यह 30 सितंबर, 2024 के अंत में 90.89 प्रतिशत था। केनरा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के. सत्यनारायण राजू ने कहा कि बैंक के पास इस गति से कारोबार बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी है और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अतिरिक्त पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है।

दुनियाभर में बजा भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का डंका, विदेशी निवेशकों के लिए बना हॉटस्पॉट

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का डंका एक बार फिर पूरी दुनिया में बजा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह और मजबूत हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों के लिए भारत आज भी एक 'हॉटस्पॉट' बना हुआ है। आरबीआई की 'सर्वे ऑफ फॉरेन लायबिलिटी एंड एसेट' 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार, भारत को मिलने वाले कुल एफडीआई का 34.3इ हिस्सा सिर्फ दो देशों अमेरिका और सिंगापुर से आया है।

रिपोर्ट बताती है कि भारत का कुल एफडीआई अब बढ़कर ?68.75 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के ?61.88 लाख करोड़ के मुकाबले 11.1इ की वृद्धि दर्शाता है। इनमें से अमेरिका का योगदान सबसे ज्यादा 20इ है, जबकि सिंगापुर 14.3इ हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। इनके बाद मॉरीशस (13.3इ), ब्रिटेन (11.2इ) और नीदरलैंड (9इ) प्रमुख निवेशकों में शामिल हैं।

आरबीआई के इस सर्वे में 45, 702 भारतीय कंपनियों के आंकड़े शामिल किए गए, जिनमें से 41, 517 ने एफडीआई या विदेशी निवेश में भागीदारी की थी।

रिपोर्ट की एक अहम झलक यह है कि अब विदेशी निवेशक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इस सेक्टर में एफडीआई का 48.4इ हिस्सा गया है, जो अब भारत की औद्योगिक क्षमता पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। यह 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद सर्विस सेक्टर विदेशी निवेशकों का दूसरा पसंदीदा क्षेत्र रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह ट्रेंड भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और वैश्विक उत्पादन केंद्र के रूप में उसकी बढ़ती भूमिका को मजबूत करता है।

सिप्ला का जुलाई-सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 3.7 फीसदी बढ़कर 1, 353.37 करोड़ रुपए

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। प्रमुख दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड का जुलाई-सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 3.7 प्रतिशत बढ़कर 1, 353.37 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का पिछले वर्ष इसी तिमाही में मुनाफा 1, 305.01 करोड़ रुपए रहा था। सिप्ला लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय 7, 589.44 करोड़ रुपए रही जो एक साल पहले इसी अवधि में 7, 051.02 करोड़ रुपए थी।

जुलाई-सितंबर तिमाही में कुल व्यय सालाना आधार पर 5, 452.57 करोड़ रुपए से बढ़कर 6, 004.86 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी सूचना के अनुसार, औषधि खंड से राजस्व 7, 291.43 करोड़ रुपए रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 6, 775.56 करोड़ रुपए था। नये उद्यमों ने 350.68 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष में यह इसी तिमाही में 319.6 करोड़ रुपए था।

भारतीय पहलवानों ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में किया शानदार प्रदर्शन, जीते सात मेडल

मनामा (बहरीन) **(एजेंसी)**। भारतीय कुश्ती दल ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में मेडलों की झड़ी लगाकर अभियान का शानदार समापन किया, जिसमें मोनी और जयवीर सिंह ने मनामा के एग्जीबिशन वर्ल्ड बहरीन में गोल्ड मेडल जीते। लड़कों के 55 किलोग्राम फ्रीस्टाइल डिवीजन में मुकाबला कर रहे जयवीर सिंह ने कल टॉप पर पहुंचने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। श्रीलंका के निमेश दुलंजना और कंबोडिया के फान चान ओउ डोम पर 10-0 की शानदार जीत दर्ज करने के बाद जयवीर ने एक कड़े क्वार्टर फाइनल में ईरान के यासीन ज़ारेज़ादेह को क्राइटेरिया के आधार पर हराया।

सेमीफाइनल में जयवीर सिंह ने कजाकिस्तान के इब्राहिम यस्ककबेक को 5-0 से हराया और गोल्ड मेडल मुकाबले में जापान के यामातो फुरुसावा के खिलाफ 6-2 की जीत के साथ अपना अभियान खत्म किया। मोनी ने भी लड़कियों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में उतना ही शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय पहलवान ने सेमीफाइनल में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जियाओहान जू को 8-0 से हराया और फाइनल में किर्गिस्तान की सेजिम कुर्मनबेकोवना ज़ोल्डोशबेकोवा को टेक्निकल सुपीरियरिटी के आधार पर 10-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता।

गौरव पुनिया ने लड़कों की 65 किलोग्राम कैटेगरी में प्रभावित किया लेकिन फाइनल में हार गए, उन्हें ईरान के मोर्तेजा हाजी मोल्लामोहम्मदी से 4-1 से हार मिली, जो अंडर-17 वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। लड़कियों की 69 किलोग्राम कैटेगरी में अश्विनी विश्नोई, जो अपनी सामान्य 65 किलोग्राम डिवीजन से ऊपर मुकाबला कर रही थीं, फाइनल में चीन की झाओ मिन से 10-3 से हारने के बाद सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।

कुश्ती में भारत के मेडलों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। अंडर-17 वर्ल्ड्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कोमल वर्मा ने लड़कियों के 49 किलोग्राम इवेंट में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मो जियाओकिंग को 3-1 से हराकर एक और पोडियम फिनिश हासिल किया, जबकि रचना ने लड़कियों के 43 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान की आइज़ान किलिचबेकोवना काबिल्बेकोवा को 11-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता।

एशियन यूथ गेम्स में भारत का कुल मेडल टैली 33 हो गया है जिसमें 6 गोल्ड, 11 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज शामिल हैं। इस बीच भारतीय पहलवानों ने कल कुल 7 मेडल जीतकर अपना अभियान खत्म किया। मंगलवार को याशिता ने कुश्ती में लड़कियों के 61 किलोग्रामप वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। वेटलिफ्टर प्रीतिस्मिता भोई और भारत की लड़कों और लड़कियों की कबड्डी टीमों ने भी गेम्स में पहले गोल्ड मेडल जीते हैं।

ब्याज दर में कटौती का असर उल्टा! निवेशकों को लगा बड़ा झटका 2.27 लाख करोड़ का नुकसान

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक 25 बेसिस प्वाइंट की ब्याज दर कटौती की है लेकिन दिसंबर की पॉलिसी में आगे कोई कटौती न होने के संकेत ने बाजार की धारणा कमजोर कर दी। इस अनिश्चितता के कारण गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। शुरुआती 40 मिनट के भीतर सेंसेक्स 500 अंक तक टूट गया और निवेशकों को 2.27 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। दोपहर 12 बजे बीएसई सेंसेक्स 460.45 अंक या 0.54इ गिरकर 84, 537.66 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 142 अंक गिरकर 25, 911.10 पर पहुंच गया। दिन के दौरान सेंसेक्स 84, 467.03 तक फिसला और निफ्टी 25, 892.25 तक गिरा, जो सत्र के निचले स्तर रहे।

सेंसेक्स पर सन फार्मा, भारती एयरटेल, पावर ग्रिड, आईटीसी, टाटा स्टील और एशियन पेंट्स में 1इ से ज्यादा की गिरावट देखी गई। वहीं, लार्सन एंड टुब्रो, अडानी पोर्ट्स और मारुति के शेयरों में मामूली बढ़त रही। सेक्टोरल इंडेक्स में हेल्थकेयर, आईटी, टेलीकॉम और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखा, जबकि बीएसई मिडकैप इंडेक्स में हल्की तेजी और स्मॉलकैप इंडेक्स में मामूली गिरावट रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों (इध्) ने बुधवार को 2, 540 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। हालांकि, इससे एक दिन पहले उन्होंने 10, 000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था। अक्टूबर में अब तक एफआईआई ने करीब 18, 000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो तीन महीने में सबसे बेहतर प्रवाह रहा है।

बॉडी शेमिंग पर भड़कीं सिडनी स्वीनी, कहा- आत्मविश्वास से भरा महसूस करती हूं, किसी को कुछ साबित नहीं करना

सिडनी स्वीनी ने उन ट्रोल्स को करारा जवाब दिया जो कह रहे थे कि उन्होंने कॉस्मेटिक प्रक्रियाएँ करवाई हैं। व्हाइट लोटस की इस अभिनेत्री ने सुइयों से अपने डर का इज़हार किया और चल रही चर्चाओं का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करवाया है। वैराइटी के साथ बातचीत में, 28 वर्षीया ने बताया, 'मैंने कभी कुछ नहीं करवाया। मुझे सुइयों से बिल्कुल डर लगता है। कोई टैटू नहीं। कुछ भी नहीं। मैं खूबसूरती से बूढ़ी हो जाऊँगी।'

अभिनेत्री ने यह भी बताया कि कैसे वह अन्य महिलाओं को बिना किसी शर्मिंदगी के अपने आत्मविश्वास को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। यूफोरिया स्टार ने कहा, 'आपको किसी भी कमरे में छिपने या ढकने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपके पास है उसे दिखाएँ और अच्छा महसूस करें।'

सिडनी स्वीनी ने अपने रूप-रंग को लेकर उड़ रही अफवाहों पर सफाई दी है। 'द यूफोरिया' और 'द व्हाइट लोटस' स्टार ने सोशल मीडिया पर उन अटकलों का जवाब दिया जिनमें कहा गया था कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है, और वह इससे पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने आगे कहा, 'मैं खूबसूरती से बूढ़ी होती जा रही हूँ, ' जिससे उनके वर्तमान रूप की तुलना उनकी किशोरावस्था की तस्वीरों से करने वाली चर्चाओं पर विराम लग गया।

हफ़्तों से, रेडिट थ्रेड्स और सोशल मीडिया यूज़र्स बोटॉक्स, फिलर्स और यहाँ तक कि नाक की सर्जरी के बारे में अटकलें लगा रहे थे, एक यूज़र ने दावा किया कि उनका ऊपरी होंठ 'काफी बड़ा' लग रहा था और दूसरे ने ज़ोर देकर कहा कि 'नाक की सर्जरी ज़ाहिर है।' ऑनलाइन छानबीन के बावजूद, स्वीनी बेफिक्र हैं।

अभिनेत्री ने कहा कि उनके बारे में लोगों की धारणा का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा पर्दे पर निभाए गए बोल्ड और जटिल महिलाओं के किरदारों से उपजा है। उन्होंने कहा, 'क्योंकि मैं कई विभाजनकारी किरदार निभाती हूँ, इसलिए लोग सोचते हैं कि वे मुझे जानते हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं करते। इसलिए जब लोग सोचते हैं, 'आह, वह एक सेक्स सिंबल है, ' या 'वह उसी की ओर झुक रही है, ' तो मैं कहती हूँ, 'नहीं, मुझे बस अच्छा लग रहा है, और मैं यह अपने लिए कर रही हूँ और मैं मज़बूत महसूस कर रही हूँ। स्वीनी ने आगे कहा कि वह अन्य महिलाओं को भी बिना किसी शर्मिंदगी के अपने आत्मविश्वास को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं। उन्होंने कहा, 'आपको किसी भी कमरे में छिपने या पर्दा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जो आपके पास है उसे दिखाएँ और अच्छा महसूस करें।'

कैप्टन अमेरिका के हीरो क्रिस इवांस बने पिता, घर आई नन्ही परी, खास है नाम

हॉलीवुड अभिनेता क्रिस इवांस, जिन्हें 'कैप्टन अमेरिका' के नाम से जाना जाता है, अब पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी, अभिनेत्री अल्बा बैप्टिस्टा ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया है। यह खबर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, हालांकि इस जोड़े की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

वेबसाइट टीएमजेड ने मंगलवार को बताया कि 'वॉरियर नन' फेम अल्बा बैप्टिस्टा ने शनिवार को एक बेटी को जन्म दिया। क्रिस और अल्बा ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स में अपनी बेटी का स्वागत किया।

पीपल मैगजीन के एक सूत्र ने बताया कि इस जोड़े ने अपनी बेटी का नाम अल्मा ग्रेस बैप्टिस्टा इवांस रखा है। सूत्र ने यह भी बताया, 'वे अपनी गोपनीयता और बच्चे के साथ एक परिवार के रूप में इन खास शुरुआती दिनों का आनंद ले रहे हैं।' क्रिस इवांस और अल्बा बैप्टिस्टा ने लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद 2023 में केप कॉड में एक निजी समारोह में शादी की थी। अल्बा की प्रेग्नेंसी की अफवाहें तब उड़ी थीं, जब जून में फादर्स डे पर एक फैन के पोस्ट पर अल्बा के पिता ने क्रिस को इशारा करते हुए कमेंट किया था कि अब तुम्हारी बारी आ रही है।

MAHATRANSCO
Maharashtra State Electricity Transmission Co. Ltd.

E.H.V. Civil Const. cum Maint. Division, Panvel
SRM e-Tender Notice No. 15/2025-26

Online bids (SRM e-Tenders) are invited for following works from the registered contractors :

SRM e-Tender No.	RFx No.	Name of work	Estimated cost in Rs.
27/2025-26	7000037979	(2nd Call) Annual civil maintenance work for 220KV Taloja, 100KV Taloja, 220KV Apta, 220KV Tambati, 100KV Khopoli and wasambe colony along with other civil works for the FY 2025-26.	2425588.00
28/2025-26	7000038000	(2nd Call) Annual civil maintenance works at 400KV Kharghar and 220KV Uran along with other civil works for the F.Y 2025-26.	2406205.00

For detailed information, please see SRM e-Tender section of our website: **www.mahatransco.in**.
Contact person: Dy. Executive Engineer (Civil), Panvel.
Telephone No. (022)27480325/ Mob no. 9765644291

Sd/-
Executive Engineer (Civil), Panvel

आग के कारण से नहीं रोका जा सकता बीमा दावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-अग्नि बीमा जोखिम प्रबंधन का अहम साधन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अग्नि बीमा पर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि फायर इंश्योरेंस केवल आग से होने वाले नुकसान की भरपाई का साधन नहीं, बल्कि यह जोखिम प्रबंधन, संपत्ति सुरक्षा और आर्थिक मजबूती का एक रणनीतिक उपकरण है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक बीमाधारक खुद आग लगाने में शामिल नहीं है, तब तक आग लगने का कारण दावा अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता और ऐसी घटनाएं बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत आती हैं।

कोर्ट ने कंपनी के दावे को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ओरियन कॉनमर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में आई है। अदालत ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि सितंबर 2010 में कंपनी के परिसर में लगी आग दुर्घटनावश थी और वह बीमा पॉलिसी के दायरे में आती है। न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कंपनी ओरियन कॉनमर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के दावे को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा, 'इस

न्यायालय का मत है कि एक बार यह साबित हो जाने पर कि नुकसान आग के कारण हुआ है और धोखाधड़ी का कोई आरोप/निर्णय नहीं है या बीमाधारक आग लगाने वाला नहीं है तो यह मान लिया जाएगा कि आग दुर्घटनावश लगी थी और वह अग्नि बीमा पॉलिसी के दायरे में आती है।'

फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, 'न्यायालय का मानना है कि अग्नि बीमा जोखिम प्रबंधन, संपत्ति संरक्षण और आर्थिक लचीलेपन के लिए एक रणनीतिक उपकरण है। अग्नि बीमा पॉलिसी आग लगने से नहीं रोकती, बल्कि आग लगने पर उसके वित्तीय प्रभाव को कम करती है। अग्नि बीमा की अवधारणा के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके संचालन के सिद्धांतों को रेखांकित करना महत्वपूर्ण है।'

फैसले में कहा गया कि यह स्थापित कानून है कि अग्नि बीमा का अनुबंध बीमित व्यक्ति को आग से होने वाले नुकसान की भरपाई करने का एक अनुबंध है। अदालत ने साफ कहा कि अगर आग जानबूझकर लगाई गई है, तो वह बीमा कवरेज के दायरे में नहीं आती। लेकिन यदि आग आकस्मिक है, तो उसका कारण जानने की जरूरत नहीं।

इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की अपील खारिज करते हुए ओरियन कॉनमर्क्स की क्रॉस अपील स्वीकार कर ली और कंपनी को ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश दिया। बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ जब 25 सितंबर 2010 को ओरियन के परिसर में आग लगी और बीमा कंपनी ने दावे को 'कारण संदिग्ध' बताते हुए खारिज कर दिया। बाद में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 2020 में कंपनी के पक्ष में आंशिक राहत देते हुए बीमा कंपनी को ?61.39 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया था। दोनों पक्षों ने इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

साइप्रस विदेश मंत्री कोम्बोस की जयशंकर से मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा, एफटीए पर पुरजोर समर्थन

नई दिल्ली। साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस तीन दिन की भारत यात्रा पर हैं। जहां दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने मुलाकात को लेकर एक्स पर पोस्ट भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि नई दिल्ली में साइप्रस के विदेश मंत्री का स्वागत कर बेहद खुशी हुई। एस जयशंकर ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने भारत-साइप्रस संयुक्त कार्य योजना 2025-2029 की समीक्षा की, जिस पर जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा के दौरान नेताओं ने सहमति व्यक्त की थी।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी चर्चाओं में वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति, हमारे संबंधित क्षेत्रों में विकास और बहुपक्षीय मंचों पर हमारे सहयोग पर भी चर्चा हुई। 2026 में साइप्रस के यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालने के साथ, हमें विश्वास है कि भारत-यूरोपीय संघ के संबंध और भी मजबूत होंगे।'

आतंकवाद के रुख पर भारत का समर्थन

वहीं साइप्रस ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल में हुए आतंकवादी हमलों के बाद भारत के साथ अपने देश की पूर्ण एकजुटता व्यक्त की। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश आतंकवाद और उसे समर्थन या वित्तपोषण करने वालों के प्रति शून्य सहनशीलता का रुख रखते हैं।

एफटीए को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया

राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में साइप्रस के विदेश मंत्री ने कहा कि साइप्रस यूरोपीय संघ (ईयू) और भारत के बीच लंबे समय से चल रहे मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के समापन का पुरजोर समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के सफल समापन से ना केवल यूरोपीय संघ-भारत संबंध मजबूत होंगे, बल्कि भारत और सभी यूरोपीय देशों के लिए अपार आर्थिक अवसर भी खुलेंगे। कोम्बोस ने साइप्रस समस्या के प्रति भारत के सिद्धांतवादी दृष्टिकोण की भी सराहना की और यूरोपीय संघ-भारत संबंधों को मजबूत बनाने के साथ-साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। बता दें कि साइप्रस जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने की तैयारी कर रहा है। ध्यान रहे कि साइप्रस समस्या से विदेश मंत्री का तात्पर्य भूमध्यसागरीय द्वीप के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में ग्रीक और तुर्किये समुदायों को अलग करने वाले बफर जोन में 1974 से चल रही अनधिकृत गतिविधियों से था। साइप्रस और तुर्की के बीच वर्तमान मुद्दा दक्षिण में ग्रीक साइप्रस और उत्तर में तुर्किये साइप्रस के बीच चल रहा विवाद है।

भारत को बताया स्वाभाविक साझेदार और सहयोगी

अपने बयान में विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस ने आगे कहा, 'हम भारत को एक स्वाभाविक साझेदार और सहयोगी के रूप में देखते हैं। आज, जब भारत एक बढ़ती हुई बहुपक्षीय दुनिया में अग्रणी आवाज के रूप में उभर रहा है, साइप्रस भारत को ना केवल एक पुराने मित्र के रूप में देखता है, बल्कि भविष्य के सहयोग के लिए एक साझेदार के रूप में भी देखता है।

बिहार में दो तिहाई बहुमत से बन रही एनडीए की सरकार - कैलाश विजयवर्गीय

पटना **(एजेंसी)**। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनावी बिगुल बज चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए अब महज़ कुछ दिन बचे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। देवास के भौंरासा में विजयवर्गीय ने एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है। बुधवार को देवास के भौंरासा पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समर्थकों ने किया कैलाश विजयवर्गीय का ज़ोरदार स्वागत किया। इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है और दो तिहाई बहुमत से बन रही है।

बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है इससे पहले भी विजयवर्गीय बिहार में एनडीए की चुनावी जीत का

दावा पेश कर चुके हैं। हालांकि बिहार में किसकी सरकार बनती है ये तो नतीजों के साथ ही स्पष्ट होगा। फिलहाल उनके इस बयान से सियासी पारा चढ़ने की संभावना है।

सरकारी नौकरियां बेचने के लिए दोबारा छापी ओएमआर शीट, आरोपियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 3 करोड़ बरामद

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में अयोग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी देने के लिए ओएमआर शीट दोबारा से छाप दी गई। जिन नौकरी मिली, उनसे पैसे लिए गए। योग्य प्रत्याशी, नियुक्ति पत्र मिलने की राह देखते रह गए। इस केस में राज्य सरकार में मंत्री, दूसरे नेता और अधिकारी, सब मिले हुए थे। परीक्षा में गड़बड़ी करने के लिए ऐसे फर्म मालिक को ओएमआर सीट की छपाई का टेंडर दिया, जो आरोपियों के इशारे पर कुछ भी कर सकता था। ओएमआर शीट बदलने के बाद अयोग्य लोगों का सरकारी नौकरी में चयन हो गया। वजह, परीक्षा में अयोग्य उम्मीदवारों के फुल नंबर आ गए। ईडी ने अब आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। वहां से 3 करोड़ रुपये की नकदी और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोलकाता जोनल कार्यालय ने नगर पालिका भर्ती घोटाले में 28-29 अक्तूबर को कोलकाता और उसके आसपास 7 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कवर किए गए परिसरों में नगर पालिका भर्ती घोटाले के मुख्य संदिग्धों/आरोपियों के सहयोगियों के कार्यालय और आवास शामिल हैं। रेडिएंट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, गरोडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जीत कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंट्स आदि के परिसरों के साथ-साथ इन कंपनियों/फर्मों के प्रमोटरों/निदेशकों के आवासों की भी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लगभग 3 करोड़ रुपये की नकदी सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तलाशी में एक कार्यप्रणाली का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत नगर पालिका भर्ती घोटाले में मुख्य संदिग्धों/आरोपियों के दागी धन को फर्जी सेवाओं की आड़ में कंपनियों/फर्मों के माध्यम से लूटा जा रहा था। ईडी ने हाल ही में 10 अक्तूबर को पश्चिम बंगाल के विधायक और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस के कार्यालय सहित 13 परिसरों पर तलाशी ली थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज के अलावा 45 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी।

ईडी जांच में सामने आया है कि इस केस

में रातोंरात ओएमआर सीट बदल दी गई। यानी उनकी नई छपाई हो गई। उसके बाद जिन अयोग्य लोगों का चयन किया जाना था, उनके नंबर फुल आ गए। दो तरह के लोगों का चयन किया गया। एक, जो अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस के करीबी थे और दूसरे, जिन्होंने किसी भी तरह से नौकरी के लिए पैसा दिया था। ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर इस केस की जांच शुरू की थी। यहां पर ये उल्लेख करना उचित है कि ईडी ने सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में 2022 के सीएएन 1 के साथ 2022 के डब्ल्यूपीए 9979 में 2023 के सीएएन 2 के रूप में एक आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया था। उसमें पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में फैले नगर पालिकाओं में विभिन्न पदों की भर्ती में की गई अवैधताओं से संबंधित अपने निष्कर्षों पर एक स्थिति रिपोर्ट रखी गई थी।

इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी द्वारा जांच के दौरान, 2023 में अयान सिल और अन्य से जुड़े विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान, अयान सिल के कब्जे से डिजिटल साक्ष्य के साथ कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। उन्हें जब्त कर लिया गया। आपत्तिजनक दस्तावेजों की जांच से पता चला था कि भर्ती घोटाला, केवल शिक्षकों की भर्ती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न नगर पालिकाओं डकांचरापाड़ा, न्यू बैरकपुर, कमरहाटी, टीटागढ़, बारानगर, हालिसहर, दक्षिण दमदम (एन), दमदम आदि. तक फैला हुआ है। जाँच में सामने आया है कि मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, क्लर्कों, चपरासी, एम्बुलेंस परिचारकों, सहायक मिस्त्रियों, पंप ऑपरेटरों, हेल्परों, स्वच्छता सहायकों और ड्राइवरों आदि की भर्ती में भी गोलमाल हुआ है।

ईडी की अब तक की गई जांच से पता चला है कि विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिकाओं आदि से संबंधित ठेके एक ही कंपनी मेसर्स एबीएस इन्फोज़ोन प्राइवेट लिमिटेड (निदेशक- अयान सिल) को प्रश्न पत्रों की छपाई, ओएमआर शीट की छपाई, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का मूल्यांकन और मेरिट सूची तैयार करने आदि के लिए दिए गए थे।

भयानक तूफान 'मेलिसा' ने मचाई भारी तबाही, 25 लोगों की मौत से पसरा मातम

हैती **(एजेंसी)**। कैरिबियाई सागर में उठा भयंकर तूफान 'मेलिसा' दक्षिणी हैती और जमैका में कहर बनकर टूटा है। इस विनाशकारी तूफान के चलते अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक तूफान 'मेलिसा' के कारण हैती में मूसलाधार बारिश हुई जिससे एक नदी का तटबंध (किनारा) टूट गया। तटबंध टूटने से पानी का भयानक सैलाब आया और उसने 25 लोगों की जान ले ली। यह इलाका पिछले एक सप्ताह से मेलिसा की लगातार बारिश से जूझ रहा था और अनुमान है कि यहाँ 12 इंच से अधिक वर्षा हुई है। हैती की नागरिक सुरक्षा एजेंसी का केवल एक ही अधिकारी प्रभावित क्षेत्र में मौजूद था। वहीं बाढ़ का पानी बढ़ने पर निवासी अपनी जान बचाने के लिए खुद ही सुरक्षित स्थानों की ओर भागते रहे।

तूफान 'मेलिसा' ने जमैका में भी भारी तबाही मचाई। तूफान के गुजर जाने के बाद जमैका के अधिकारियों ने तूफान से प्रभावित सेंट एलिजाबेथ पैरिश से चार शव बरामद किए हैं। पूरे द्वीप में लोगों को बचाने और मदद पहुंचाने का काम (रेस्क्यू ऑपरेशन) तेजी से जारी है।

देश की मुख्य बिजली कंपनी जमैका पब्लिक सर्विस ने जानकारी दी है कि वह बिजली ग्रिड (पूरे सिस्टम) को हुए नुकसान का जायजा ले रही है। यह आकलन बिजली बहाल करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर बताया कि इससे उन्हें सबसे सुरक्षित और तेज तरीके से बिजली बहाल करने के लिए जरूरी सारी जानकारी मिल जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जमैका का लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि तूफान आने से पहले ही देश का बिजली तंत्र दबाव में था।

तूफान मेलिसा ने मंगलवार को जमैका में सैफिर-सिम्पसन पैमाने पर श्रेणी 5 के एक शक्तिशाली तूफान के रूप में प्रवेश किया था। यह इस पैमाने पर सबसे अधिक तीव्रता होती है जो विनाशकारी तबाही मचाती है। जांच एजेंसियाँ नुकसान की पूरी सीमा का आकलन कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र के अनुसार यह तूफान सोमवार की सुबह श्रेणी 3 के तूफान के रूप में क्यूबा पहुंचा था लेकिन बुधवार दोपहर तक मेलिसा लगभग 100 मील प्रति घंटे की लगातार हवाओं के साथ श्रेणी 2 के तूफान में कमजोर हो गया है।

रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दो शहरों की घेराबंदी की, कहा- सरेंडर कर दो वर्ना कार्यवाही होगी तेज

मॉस्को **(एजेंसी)**। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को दावा किया कि रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के दो प्रमुख पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना को घेर लिया है और उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा है, वहीं यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों ने पुतिन के इस दावे का खंडन किया है। पुतिन ने मॉस्को के एक सैन्य अस्पताल में घायल सैनिकों के साथ बातचीत में कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेन और पश्चिमी देशों के पत्रकारों के लिए सुरक्षित गलियारे खोलने के लिए तैयार है ताकि वे ''अपनी आंखों से देख सकें कि क्या हो रहा है।'' रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के एक प्रमुख गढ़ पोक्रोवस्क और उत्तर-पूर्वी खार्किव क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण रेल जंक्शन कुपियांस्क में यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया गया है। वहीं पुतिन के दावों से ठीक उलट यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने कहा कि कुपियांस्क को घेर लिए जाने के दावे 'मनगढ़ंत और काल्पनिक' हैं। यूक्रेन की पूर्वी सेना के प्रवक्ता ह्रीहोरी शापोवाल ने कहा कि पोक्रोवस्क में हालात ''कठिन लेकिन नियंत्रण में हैं।'' पोक्रोवस्क की रक्षा कर रही यूक्रेनी सेना की '7वीं रैपिड रिएक्शन कोर' ने कहा है कि रूस ने शहर को घेरने के लिए लगभग 11, 000 सैनिकों को तैनात किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उसने स्वीकार किया कि कुछ रूसी सैन्य इकाइयां पोक्रोवस्क में घुसपैठ करने में कामयाब रही हैं। पुतिन ने बुधवार को संकेत दिया कि रूस दोनों शहरों में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों के आत्मसमर्पण के बदले कोई समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों का दौरा करने से पत्रकारों को ''घेरे गए यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति का पता चल सकेगा और यूक्रेन का राजनीतिक नेतृत्व अपने नागरिकों के भविष्य के बारे में उचित निर्णय ले सकेगा।'' वाशिंगटन के एक थिंक टैंक 'इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर' ने मंगलवार देर रात कहा कि रूसी सेना पोक्रोवस्क क्षेत्र में आगे बढ़ गई है लेकिन पोक्रोवस्क शहर के भीतर किसी भी मोर्चे पर उनका नियंत्रण नहीं है।

अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा, गर्भगृह के दरवाजे से सोना गायब करने का आरोप

तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोटी को गुरुवार को रन्नी की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में पेशी कराई।

एसआईटी ने दोपहर के समय पोटी को रन्नी की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी से पूछा कि क्या उसे जांच टीम से कोई शिकायत है, जिस पर पोटी ने इनकार किया। हालांकि, उसने यह बताया कि वह कई बीमारियों से जूझ रहा है और नियमित रूप से दवा ले रहा है। इस पर सरकारी वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि जेल में उसके लिए उचित चिकित्सा जांच और इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि सबरीमाला मंदिर से गायब सोने के एक अन्य मामले में पोटी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। अदालत ने इस संबंध में निर्देश दिए कि सोमवार को उसे फिर से अदालत में पेश किया जाए। इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उसे तिरुवनंतपुरम की विशेष जेल में शिफ्ट कर दिया गया।

उन्नीकृष्णन पोटी पर आरोप है कि उसने मंदिर के 'द्वारपालक' मूर्तियों के सोने से मढ़े तांबे के प्लेटों से सोना चोरी किया था। इसके अलावा, सबरीमाला मंदिर के गर्भगृह (श्रीकोविल) के दरवाजे के फ्रेम से भी सोना गायब होने का मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और जांच में कई नए पहलू सामने आ सकते हैं।

अन्य अधिकारी भी रडार पर

इस मामले में सबरीमाला के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी. मुरारी बाबू भी जांच के घेरे में हैं। पुलिस ने उन्हें चार दिन की हिरासत में रखा है ताकि चोरी की साजिश और अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिल सके।

ट्रंप ने दिए संकेत- कनाडा संग रिश्तों में नरमी संभव, कहा-'बहुत अच्छी बातचीत हुई'

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ 'बहुत अच्छी बातचीत' की है, जो दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव में नरमी का संकेत देती है। यह बयान उन्होंने एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान डिनर मीटिंग के बाद दिया। बीते हफ्ते ट्रंप ने कनाडा पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के एक 'फेक विज्ञापन' को लेकर तीखा हमला किया था। यह विज्ञापन 26 अक्टूबर को एमएलबी वर्ल्ड सीरीज़ के दौरान दिखाया गया था, जिसमें कहा गया कि रीगन ने टैरिफ (आयात शुल्क) का विरोध किया था।

ट्रंप ने इसे 'धोखाधड़ी' करार देते हुए कनाडा के आयात पर 10इ अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की थी।विज्ञापन'ाज्दूत्ब ओंटारियो सरकार द्वारा 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तैयार किया गया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच 'ट्रूथ सोशल' पर लिखा, 'रीगन ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए टैरिफ का समर्थन किया था, लेकिन कनाडा ने झूठ फैलाया। उनका विज्ञापन तुरंत हटाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसे प्रसारित होने दिया।'वर्तमान में कनाडा के कई उत्पादों पर 35इ तक टैरिफ, स्टील और एल्युमिनियम पर 50इ, और ऊर्जा उत्पादों पर 10इ शुल्क लागू है।

ट्रंप ने यह नहीं बताया कि नई वृद्धि किन उत्पादों पर लागू होगी। अक्टूबर की शुरुआत में दोनों नेताओं की वॉशिंगटन में मुलाकात के बाद संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। तब ट्रंप ने कहा था कि 'कनाडा के साथ समझौता अमेरिका के किसी भी अन्य व्यापार समझौते से अधिक जटिल है।' इसके बाद ट्रंप ने एशिया यात्रा से पहले कार्नी से मिलने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि, बुसान में बुधवार रात हुए डिनर के दौरान दोनों नेताओं के बीच संक्षिप्त बातचीत से ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका-कनाडा रिश्तों में कड़वाहट कम हो सकती है।

ट्रंप ने फिर गिराई भारतीयों पर गाज! ऑटोमैटिक वर्क परमिट एक्सटेंशन सुविधा अचानक की समाप्त

वाशिंगटन **(एजेंसी)**। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने घोषणा की है कि अब ऑटोमैटिक एक्सटेंशन की सुविधा समाप्त कर दी गई है, जिसके अनुसार विदेशियों को अपने वर्क परमिट (रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ ईएडी) के लिए रिन्यूअल आवेदन देने पर स्वचालित रूप से जारी रखा जाता था। यह नया नियम 30 अक्टूबर 2025 से लागू हो गया है। पुराने नियम के तहत, जब कोई विदेशी ईएडी रिन्यूअल के लिए समय पर आवेदन करता था, तो रिन्यूअल मंजूर होने तक अबः यदि आवेदन 30 अक्टूबर 2025 या उसके बाद किया गया है, तो स्वचालित एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वर्तमान ईएडी की अवधि समाप्त होने के बाद पुनः स्वीकृति मिलने तक काम करना वैध नहीं रहेगा। कुछ श्रेणियों को इस नियम से अपवाद मिल सकता है।

इस बदलाव से विशेष रूप से, भारतीय मूल के पेशेवरों पर इस नियम का बहुत बड़ा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि वे अमेरिका में तकनीकी, शोध, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएचएस ने कहा है कि यह कदम 'विदेशी कामगारों के पुनः परमिट देने से पहले बेहतर स्क्रीनिंग और सत्यापन सुनिश्चित करने' के लिए उठाया गया है। यूएससीआईएस के निदेशक जोसेफ एडलो ने कहा कि 'संयुक्त राज्य में काम करना - एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है।'

ईएडी रिन्यूअल के आवेदन को कम-से-कम 180 दिन पहले सबमिट करना बेहतर रहेगा। रिन्यूअल मंजूरी मिलने तक काम जारी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लॉजिस्टिक ??? से नौकरी और वीज़ा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं।नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी के पास सक्रिय और वैध ईएडी हो, अन्यथा काम जारी रखना गैरकानूनी हो सकता है। इस तरह, यह नीति परिवर्तन अमेरिका में काम कर रहे लाखों विदेशी कर्मचारियों, विशेष रूप से भारतीय पेशेवरों और उनके परिवारों की स्थिति को अत्यधिक अस्थिर बना सकता है।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.phpid=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharatt=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. MAHHIN/ 2016/65841 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा AIS Printing solution प्लॉट नं0-A- 544 TTC इंडस्ट्रियल एरिया एमआईडीसी माहपे-नवी मुंबई, थाने 400709 से मुद्रित एवं शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012प्रकाशित एवं सम्पादित । कार्यालय : शाप.नं. 36, द्वितीय तल, प्लाट -490.1. जाम मील बिल्डिंग, डॉ बाबा साहेब अम्बेकर रोड, लाल बाग परेल, मुम्बई-400012 । फोन : 022-24706563 । कार्यकारी सम्पादक- योगेन्द्र चौधरी
E-Mail : editormantrabharat@gmail.com mantrabharatmumbai@gmail.com । सम्पादक : विनोद आर शर्मा, मोबाइल : 7007837917 । समूह सम्पादक : डॉ दयानन्द तिवारी। वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे के लिए मंत्र प्रधान कार्यालय क्षेत्र प्रयागराज/इलाहाबाद न्यायालय ही होगा। प्रधान कार्यालयः 80ए मेंहदौरी, तेलियरगंज, प्रयागराज-211004 (नोटः कानूनी पत्र व्यवहार का पता प्रधान कार्यालय ही होगा।)